A Daily News Magazine
इंदौर
शुक्रवार, 06 दिसंबर, 2024

सुबह सवेरे

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 69, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2 (डाक पंजीयन संख्याः MP/IDC/1529/2016-2018)

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

भारत-बांग्लादेश : 'भरोसेमंद दोस्ती' में कैसे पड़ती जा रही दरार

अंशुल सिंह

आज से दस साल पहले नरेंद्र मोदी पहली बार बतौर प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दे रहे थे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था, 'हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने को प्राथमिकता दी है।'

पीएम मोदी ने इस अमेरिकी दौरे के बीच न्यूयॉर्क में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना से अपनी पहली मुलाक़ात भी की थी। फिर अगले दस सालों तक मोदी और शेख़ हसीना के बीच द्विपक्षीय मुलाक़ातों की संख्या बढ़ती गई और भारत-बांग्लादेश के संबंधों का ग्राफ़ भी ऊपर चढ़ता गया।

इसी साल जून में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और जनवरी में शेख़ हसीना पांचवीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं थी। मोदी के शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद शेख़ हसीना भारत आईं। लगभग डेढ़ महीने बाद शेख़ हसीना एक बार फिर भारत आईं लेकिन बतौर प्रधानमंत्री नहीं। इस बार जब वह भारत पहुंचीं तो बांग्लादेश में लाखों छात्र और लोग सड़कों पर थे। शेख़ हसीना ने इस्तीफ़ा दिया और बांग्लादेश में 84 वर्षीय नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली। अंतरिम सरकार के बनने के बाद भारत-बांग्लादेश के संबंधों में कड़वाहट शुरू हुई और अब चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ़्तारी के बाद दोनों देशों के बीच काफ़ी तल्ख़ कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है।

बीते दिनों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरूल ने अपने फ़ेसबुक पोस्ट में लिखा, 'भारत को ये समझना होगा कि ये शेख़ हसीना का बांग्लादेश नहीं है।'

बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को भारत समर्थक के तौर पर देखा जाता रहा है। भारत और बांग्लादेश चार हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं और दोनों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। बांग्लादेश को 'इंडिया लॉक्ड' देश कहा जाता है।

बीते कुछ सालों में बांग्लादेश, भारत के लिए एक बड़ा बाज़ार बनकर उभरा है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2022-23 में बांग्लादेश भारत का पांचवां सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार बन गया। वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 15.9 अरब डॉलर का था।

रिटायर्ड भारतीय राजनियक और बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे पिनाक रंजन चक्रवर्ती कहते हैं, 'शेख़ हसीना के समय भारत कंधे से कंधा मिलाकर बांग्लादेश के साथ आगे बढ़ रहा था। दोनों देश के संबंध भी ऐतिहासिक गति से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं।' भारत और बांग्लादेश ने साल 2015 में भूमि सीमा समझौते तथा क्षेत्रीय जल पर समुद्री विवाद जैसे अरसे से लंबित मुद्दों को सफलतापूर्वक सुलझाया था। लेकिन उस दौर में भी सीमा पार नदी के जल का बंटवारा, अवैध प्रवास, नशीले पदार्थों की तस्करी और बांग्लादेश पर चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता की बात थी।

भारत और बांग्लादेश 50 से ज़्यादा नदियां साझा करते हैं, लेकिन अब तक केवल दो संधियों (गंगा जल संधि और कुशियारा नदी संधि) पर सहमति बनी है। तीस्ता और फेनी नदी के मुद्दे पर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है।

शेख़ हसीना के जाने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। येल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर सुशांत सिंह इसे भारत की कूटनीतिक विफलता मानते हैं। सुशांत सिंह के अनुसार ' हसीना ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया और सेना सहित सभी सरकारी संस्थाओं को नियंत्रित किया। परिणामस्वरूप, भारत ने मान लिया कि विरोध के बावजूद वह सत्ता में रहेंगी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भारतीय ख़ुफ़िया और कूटनीतिक विफलता के कारण भारत तब हैरान रह गया, जब सेना ने इस महीने (अगस्त) हसीना को देश छोड़ने के लिए कहा। किसी भी पश्चिमी सरकार ने उन्हें शरण देने की पेशकश नहीं की, जिससे वह नई दिल्ली में ही रह गईं।'

सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख़ हसीना के फ़ैसलों को पलटना शुरू किया और महीने भर के भीतर जमात-ए-इस्लामी पर लगी पाबंदी हटा दी। तब जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफ़ीक़-उर रहमान ने कहा था, 'हमारा मानना है कि भारत अंततः बांग्लादेश के साथ संबंध में अपनी विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन करेगा। हमें लगता है कि एक-दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए।' शेख हसीना जमात-ए-इस्लामी को आतंकवादी संगठन बताती थीं।

प्रोफ़ेसर हर्ष वी पंत, नई दिल्ली स्थित ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष हैं। जमात के सवाल पर प्रोफ़ेसर पंत कहते हैं, 'शेख़ हसीना से पहले भी बीएनपी और जमात खुलकर भारत विरोधी स्टैंड लेते थे। वो कोशिश करते थे कि इस्लामिक कट्टरपंथियों में अपनी पकड़ मज़बूत कर पाएं और भारत विरोधी भावना को भुनाकर अपनी राष्ट्रवादी भावना को मज़बूती दे सकें। दोनों आज भी यही कर रहे हैं और भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए।'

बांग्लादेश में जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं भारत के ख़िलाफ़ आक्रामकता बढ़ती जा रही है। अब चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ़्तारी के बाद हालात और ख़राब होते दिख रहे हैं। भारत की तरफ़ से लगातार कहा गया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए।

'बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में हिन्दू आठ प्रतिशत हैं। मंगलवार को बीएनपी के महासचिव रुहुल कबीर रिज़वी ने भारत की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि हम भारत के ग़ुलाम बनने के लिए आज़ाद नहीं हुए हैं। हम भारत के उग्र हिन्दुओं से कहना चाहते हैं कि आपकी दोस्ती शेख़ हसीना से है।'

ऐसे माहौल में सवाल उठता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध पटरी पर कब लौटेंगे?

प्रोफ़ेसर पंत कहते हैं, 'यूनुस सरकार की कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। जब तक वहां चुनाव नहीं होते तब तक बड़ा मुश्किल है कि भारत-बांग्लादेश संबंध पटरी पर लौटें।'

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बार-बार इस बात पर ज़ोर दे रही है कि भारत सरकार को बांग्लादेश को अवामी लीग के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प मौजूद हैं? बांग्लादेश में मेजर जनरल (रिटायर्ड) एएनएम मुनीरुज़्ज़मां बातचीत में कहते हैं कि 'भारत को बांग्लादेश के राजनीतिक क्षेत्र में सभी पक्षों के साथ बातचीत करना चाहिए। पांच अगस्त के घटनाक्रम के बाद, बांग्लादेश की राजनीति बहुत अलग हो गई है।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र के एक 'नाथ'

पीएम मोदी की मौजूदगी में ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

शिंदे और अजित पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानस्भा चुनावों में महायुति की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने 11 दिन बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 22 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। देवेंद्र फडणवीस को 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। गुरुवार को शपथ लेने से पहले फडणवीस सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया था। इसके बाद उन्होंने गौमाता की पूजा भी की थी। शपथ समारोह में पहले देवेंद्र फडणवीस और फिर उनके बाद एकनाथ शिंदे व अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे।

10 के पक्ष में किया मतदान, 3 गाजा प्रस्तावों से बनाई दूरी

एस जयशंकर ने भारत-फिलस्तीन मुद्दे पर बताया भारत का रुख

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इजरायल-फलस्तीन के मुद्दे पर भारत के रुख पर बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत इजराइल-फलस्तीन मुद्दे पर दो-राष्ट्र समाधान का समर्थक है। जयशंकर ने राज्यसभा में बताया कि भारत ने यूएन में फलस्तीन पर 13 में से 10 प्रस्तावों का समर्थन किया है। भारत फलस्तीन को मानवीय सहायता भी भेज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुद्दे पर कई विश्व नेताओं से बात की है। एस जयशंकर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि भारत, इजराइल और फलस्तीन दोनों के साथ एक स्वतंत्र और सुरक्षित देश के रूप में रहने के पक्ष में है। उन्होंने साफ किया कि 7 अक्टूबर से अब तक यूएन में फलस्तीन पर 13 प्रस्ताव आए हैं। इनमें से भारत ने 10 का समर्थन किया है और 3 पर अलग रहा है। जयशंकर ने कहा, भारत की फलस्तीन के प्रति नीति लंबे समय से चली आ रही है।

मुख्यमंत्री नई दिल्ली में 'कर्मभूमि से जन्मभूमि' सम्बंधी त्रिपक्षीय बैठक में हुए शामिल

बूंद-बूंद जल बचाने का अभियान प्रशंसनीय : मुख्यमंत्री यादव

राज्यों के सहयोग से होगा सफल क्रियान्वयनः केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री पाटिल

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्षा जल को संग्रहित कर भूगर्भ में जल भंडारण क्षमता के विकास के लिए चलाई जा रही 'कर्मभूमि से जन्मभूमि' योजना एक अभिनव पहल है। इस योजना में गुजरात में रहकर व्यापार करने वाले अन्य प्रदेशों के व्यापारियों द्वारा स्वयं के संसाधनों से अपने राज्यों में बोर लगवाने का काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के सतना जिले में इस योजनांतर्गत कार्य आरम्भ हो गया है। प्रसन्नता की बात है कि योजना में पूरे प्रदेश में 15 हजार बोर लगाने का लक्ष्य है। शासकीय संसाधनों के बिना गुजरात व्यापार करने वाले व्यापारियों की भागीदारी से चल रहा बूंद-बूंद जल

बचाने का यह अभियान प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के साथ 'कर्मभूमि से जन्मभूमि' कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर त्रिपक्षीय बैठक की।

योजना के क्रियान्वयन के लिये बैठक में जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से योजना को पूरा करने और इसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जलसंचय संकल्प को जन-आंदोलन बनाने के क्रम में 'कर्मभूमि से जन्मभूमि' कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। इसमें गुजरात में रह रहे मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार के व्यवसायी अपनी जन्म भूमि में जल संचय के उद्देश्य से बोर की व्यवस्था कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसमें राजस्थान में एक लाख 60 हजार और मध्यप्रदेश में 15 हजार बोर बनवाए जाने है। बिहार राज्य के 10 जिलों में प्रत्येक गांव में 4 बोर बनवाए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने राज्यों के सहयोग से इस योजना के सफल क्रियान्वयन की आशा व्यक्त की।

कलेक्टर होंगे स्कीम के नोडल ऑफिसर

दिल्ली में हुई बैठक के बाद केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे काम में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी और योजना को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार को होगा फायदा

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण संकल्प को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से 'कर्मभूमि से जन्मभूमि' कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। इसमें गुजरात में रह रहे मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के व्यापारी अपनी जन्मभूमि में जल संचय के लिए बोरवेल की व्यवस्था कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत राजस्थान में 1 लाख 60 हजार, मध्य प्रदेश में 15 हजार और बिहार के 10 जिलों में प्रत्येक गांव में 4 बोरवेल बनवाने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों के सहयोग से इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने की उम्मीद जताई।

सुप्रभात

है भले ही रीत जग की,
कौन जीता कौन हारा
पर सुमंगल गीत बस हम,
दूब जैसा मन हमारा
हम तुम्हें बाहर मिलेंगे
इस जगत के व्याकरण से
पारदर्शी आचरण है
बाहरी हर आवरण से
हंस जैसा हो गया मन,
चुग रहा बस प्रेम प्यारा
है भले ही रीत जग की,
कौन जीता कौन हारा
नीलकंठी स्वर भले है
इस जगत की पीर गाकर
पर सुधा हम बांटते है
नेह का चंदन लगाकर
हम नहीं जो ढूंढते हों भाग्य
का उज्ज्वल सितारा
है भले ही रीत जग की,
कौन जीता कौन हारा।

- यशोदा नैलवाल

दिल्ली मार्च को लेकर किसान संगठनों में ही फूट

नई दिल्ली (एजेंसी)। नोएडा के बाद पंजाब के किसान अब दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब के किसान संगठनों ने पहले ही ऐलान किया था कि वह 6 दिसंबर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। भारतीय किसान यूनियन (सिद्धूपुर) के जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की ओर से इसका ऐलान किया गया था। कूच से पहले ही किसान संगठनों में इसे लेकर फूट देखने को मिल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा की ओर से बयान सामने आया है कि वह इस मार्च का हिस्सा नहीं होंगे। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर ऑल इंडिया किसान सभा का बयान सामने आया है। किसान सभा की ओर से कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा इस मार्च में शामिल नहीं होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के चीफ गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा है कि इस मार्च के लिए ना तो उनसे संपर्क किया गया और ना ही उनकी सलाह ली गई। इसलिए उनका संगठन इस मार्च में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले उनकी ओर से मार्च को समर्थन देने की कोशिश की गई थी लेकिन अब काफी कुछ बदल गया है। अब वह अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं तो इन मामलों में वह दखल नहीं देंगे। वहीं भारतीय किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुरेश कोथ का कहना है कि हमारा संगठन एसकेएम से जुड़ा है। हालांकि शंभू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन से उनका कोई लेनादेना नहीं है।

इसरो का कमाल

प्रोबा-3 मिशन की सक्सेसफुल लॉन्चिंग

इसके जरिए सूर्य की स्टडी की जाएगी, अंतरिक्ष मौसम की जानकारी मिलेगी

श्रीहरिकोटा (एजेंसी)। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने गुरुवार को प्रोबा-3 मिशन लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन को गुरुवार शाम 4.04 बजे बजे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। ये मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इसका उद्देश्य दो उपग्रहों- कोरोनोग्राफ और ऑकुल्टर के जरिए सूर्य के बाहरी वातावरण की स्टडी करना है। इसरो इस मिशन को बुधवार शाम 4.08 बजे लॉन्च करने वाला था, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण इसकी लॉन्चिंग को एक दिन टाल दिया था। दोनों सैटेलाइट एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पर रहेंगे दोनों सैटेलाइट पृथ्वी की अण्डाकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे। पृथ्वी से इनकी सबसे ज्यादा दूसरी 60,530 किमी और सबसे कम दूसरी लगभग 600 किमी होगी। इस कक्षा में दोनों सैटेलाइट एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी रखने में सक्षम होंगे और एक यूनिट की तरह काम करेंगे। ऑकुल्टर सैटेलाइट में 1.4-मीटर की ऑकुलेटिंग डिस्क लगी है जिसे सूर्य की चमकदार डिस्क को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे कृत्रिम सूर्य ग्रहण होता है। इस छाया के भीतर कोरोनाग्राफ सैटेलाइट अपने टेलीस्कोप से सोलर कोरोना का निरीक्षण करेगा। प्रोबा-3 का प्राइमरी गोल स्पेस वेदर के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है, जिसमें सौर तूफान और कोरोनल मास इजेक्शन शामिल हैं। इस मिशन में दो सैटेलाइट के जरिए स्पेस एजेंसी अपनी एडवांस्ड फॉर्मेशन-फ्लाइंग टेक्नोलॉजीज को भी वैलिडेट करना चाहती है। प्रोबा-3 के जरिए वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते हैं कोरोना सूर्य की सतह से अधिक गर्म क्यों है और सौर हवा कैसे तेज होती है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 18 °c | न्यूनतम 13°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शुक्रवार, 06 दिसंबर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

चौथे मेकांग-गंगा धम्मयात्रा पर थाईलैंड से आये प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात

पटना। मेकांग बेसिन से गंगा तक चौथे धम्म यात्रा समूह की विगत दिवस बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात हुई। इस अवसर पर बोधिकायाविचलाई संस्थान 980 के महासचिव डॉ. सुपाचाई वीरापुचोंग विशेष रूप मौजूद थे। इस अवसर पर बोधिकायाविचलाई संस्थान 980 के महासचिव डॉ. सुपाचाई वीरापुचोंग ने कहा कि चौथी धम्म यात्रा परियोजना भारतीय उपमहाद्वीप पर हुई। जिसे घर माना जाता है क्योंकि 18 साल पहले, मैंने इस भूमि पर दीक्षा देना शुरू किया था। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चौथे मेकांग-गंगा धम्मयात्रा पर थाईलैंड से आये प्रतिनिधिमंडल के स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की संपत्ति है। सनातन और बौद्ध धर्म में कोई भिन्नता नहीं है। भारत और थाईलैंड आध्यात्मिक रूप से एक हैं। आगामी वर्षों में पूरा विश्व भगवान बुद्ध के विचारों का अनुसरण करेगा।

कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म भारत का का विश्व को अनुपम देन है। आज जब पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका से जुझ रहा रहा है, ऐसे में भगवान बुद्ध के विचार अत्यन्त प्रासंगिक हैं। भगवान बुद्ध ने हमें एक-दूसरे के साथ प्रेम करना सिखाया। उन्होंने अहिंसा और सद्भावना की सीख दी। आगामी वर्षों में पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के विचारों का अनुसरण करेगी, क्योंकि इसी में विश्व का कल्याण निहित है।

राज्यपाल ने इस वर्ष के फरवरी माह की अपनी थाईलैंड यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध और उनके दो प्रमुख शिष्यों- अरिहंत सारिपुत्त और अरिहंत मौदग्लयायन के पवित्र अवशेषों के पहुँचने पर वहाँ के लोग काफी भावुक थे और उन्हें थाईलैंड के चार प्रान्तों में दर्शन के लिए 25 दिनों तक रखा गया। उन्हें लगा कि स्वयं भगवान बुद्ध ही वहाँ पहुँच गये हैं। राज्यपाल की थाईलैंड की यह यात्रा तीसरी गंगा-मेकांग पवित्र अवशेष धम्मयात्रा थी। चौथी यात्रा पर थाईलैंड का प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि भारत और थाईलैंड में भौगोलिक रूप से अंतर भले हो, परन्तु आध्यात्मिक रूप से हम एक हैं और सांस्कृतिक रूप से काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। यह सदी एशिया की है। थाईलैंड में काफी लोग हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। सनातन और बौद्ध धर्म में कोई मौलिक भिन्नता नहीं है। कार्यक्रम को श्री सुपाचाई वीरापुचोंग एवं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महासचिव श्री जांगचुप छोड़ेन ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर चौथे मेकांग-गंगा धम्मयात्रा पर थाईलैंड से आये प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण, राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री रॉबर्ट एल. चोंग्यू, राज्यपाल सचिवालय के पदाधिकारीगण एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

सुखबीर बादल पर फायरिंग, अकाली दल ने पुलिस को घेरा

- मजीठिया का दावा-एक दिन पहले एसपी हमलावर आतंकी से मिले

अमृतसर (एजेंसी)। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर फायरिंग को लेकर शिरोमणि अकाली दल और पंजाब पुलिस व एएपी सरकार आमने-सामने हो गए हैं।

एक तरफ सीएम भगवंत मान से लेकर समूची एएपी लीडरशिप और मंत्री पंजाब पुलिस को सुखबीर की जान बचाने का क्रेडिट दे रहे है। वहीं अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने कहा कि वह फायरिंग की घटना की सुखबीर के प्रति सहानुभूति के एंगल से जांच करेंगे। इसके बाद अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने गोल्डन टेंपल का एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया। इसमें उनका दावा है कि 4 दिसंबर को हुए हमले से एक दिन पहले 3 दिसंबर को अमृतसर पुलिस के एसपी हरपाल सिंह आतंकी हमलावर आतंकी नारायण सिंह चौड़ा से मिले थे। अकाली नेता परमबंस सिंह रोमाणा ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए कि एसपी ने चौड़ा से हाथ मिलाया। उसके साथ बात की। आखिर चौड़ा को उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इसको लेकर अभी अमृतसर पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं सुखबीर बादल हमले के बाद आज गुरुवार को रोपड़ स्थित तख्त श्री केसगढ़ साहिब में सेवादार की सजा भुगतने पहुंचे हैं। यहां पंजाब पुलिस ने उन्हें थ्री लेयर सिक्योरिटी दी है। सुखबीर के इर्द-गिर्द पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा बनाया गया है।

संक्षिप्त समाचार

बड़ी खुशखबरी!

लखनऊ से भोपाल का सफर सिर्फ 8 घंटे में होगा पूरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों के बड़ी खुशखबरी आने वाली है। दोनों राज्यों के राजधानियों को जोड़ने के लिए बहुत जल्द एक्सप्रेस वे मिलने वाला है। उम्मीद है कि अगले साल ये एक्सप्रेस वे लोगों के लिए चालू हो जाएगी। लखनऊ से भोपाल की दूरी करीब 600 किमी है। जिसको तय करने में अभी 14 से 15 घंटे का समय लगता है। लेकिन इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने के बाद यह समय घटकर महज 7 घंटे हो जाएगी। जिससे यात्रा करने वाले फर्राटेदार तरीके से सफर कर

सकेंगे। दोनों राजधानियों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेस-वे को 3 अलग-अलग फोर और सिक्स लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा। जिसको लेकर काम चल रहा है। इसके लिए कानपुर-कबरई हाईवे, कबरई-सागर हाईवे और सागर भोपाल हाईवे के जरिए तीन हिस्सों के तहत बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने से जहां भोपाल और लखनऊ को जोड़ा जा रहा है वहीं बुंदेलखंड को भी दोनों राजधानियों से सीधे जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेस-वे को यमुना एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर बनाया जा रहा है।

चीता प्रोजेक्ट के लिए बनाए बाड़े में आग

गांधीसागर में मौके पर पहुंचे वन अधिकारी आसपास से बुलाई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां

गरोठ (नप्र)। मंदसौर जिले के गांधीसागर अभयारण्य में चीता प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए बाड़े

में आग लग गई। गुरुवार शाम करीब 4 बजे लगी आग लगातार फैल रही है। आग पर काबू पाने के लिए पास के नगर भानपुरा, रामपुरा और मनासा की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची हैं। यह इलाका अभयारण्य के चेनपुरिया गांव (रावलीकुड़ी) में आता है। आग लगने की सूचना मिलने पर वन अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क के बाद अब मंदसौर जिले के गांधीसागर अभयारण्य में चीता प्रोजेक्ट के तहत चीते बसाने की योजना है। यहां जोरशोर से इसकी तैयारी भी चल रही है।

तेज रफ़्तार बाइक ने भाई-बहन को मारी टक्कर

5 साल के मासूम की मौत, पिता के साथ टहलने निकले थे बच्चे

भोपाल (नप्र)। भोपाल के ईटखेड़ी इलाके के एक गांव में अपने पिता के साथ जा रहे भाई-बहन को एक बाइक ने टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट आने के कारण 5 साल के भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बहन गंभीर रुपए से घायल हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए रवाना किया। घटना बुधवार शाम की है, पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है एसआई रिंकू जाटव ने बताया कि मजदूरी करने वाला वीरू यादव बीनापुर गांव में रहता है। बुधवार की शाम अपने गांव से गोलखेड़ी की ओर पैदल जा रहे थे। वीरू के साथ उनका पांच साल का बेटा राज यादव व दो साल की बेटी आरोही भी थी। रास्ते में पीछे से आए तेज रफ़्तार बाइक सवार ने राज व आरोही को टक्कर मार दी। बाइक की चपेट में आने के कारण राज थोड़ी दूर तक घिसटा जबकि आरोही वहीं पर गिर गई।

इंदिरा दांगी को हिंदी भवन का प्रतिष्ठित सम्मान

भोपाल। डॉ. इंदिरा दांगी को हिंदी भवन भोपाल, मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति का प्रतिष्ठित सम्मान 'स्व. श्रीमती संतोष बत्ता स्मृति पुरस्कार 2024' दिए जाने की घोषणा हुई है। सम्मान के अंतर्गत शाल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र के साथ इक्कीस हज़ार रुपए की राशि भेंट की जाएगी। यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के उनके उपन्यास विपश्यना के लिए उन्हें दिया जाएगा जो दो सहेलियों के जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी है। साथ ही, भोपाल गैस कांड की विभीषिका को भी इसमें उकेरा गया है।

इंदिरा दांगी की कहानी, उपन्यास और नाटक विधा में अब तक 10 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनके लिखे नाटकों का अमेरिका, कनाडा आदि देशों में मंचन हुआ है। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार साहित्य अकादमी (युवा) सहित विभिन्न राज्य सरकारों के पुरस्कार सहित लगभग 3 दर्जन पुरस्कार प्राप्त हैं। इंदिरा दांगी के लिखे साहित्य पर अनेक शोध कार्य संपन्न हो चुके हैं। देश के विभिन्न विश्व विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में दांगी की कहानियां पढ़ाई जाती हैं। वे वर्ष 2022 में पद्मश्री के लिए नामांकित हुईं। उनकी कहानियों का 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अन्य भाषाओं में किताबें अनूदित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके साहित्य पर प्रश्न पूछे जाते हैं।

मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, राजगढ़, मनावर, देपालपुर में व्यापारियों पर इनकम टैक्स की रेड

धार के मनावर में कई व्यापारियों के ठिकानों पर चल रही कार्रवाई

इंदौर, धार (नप्र)। मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर के बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी, प्रॉपर्टी ब्रोकर और पेट्रोल पंप व्यवसायी सहित अन्य व्यापारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा गुरुवार अल सुबह 25 आयकर अधिकारियों की टीम ने इंदौर, देपालपुर, मनावर, राजगढ़ सहित 12 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। इंदौर के कालानी नगर में कपास कारोबारी सुरेश मेहता के घर भी आयकर विभाग की टीम पहुंचकर जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम को इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। जांच के बाद आज व्यापारियों के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया। इनमें मनावर के बड़े बिल्डिंग मटेरियल के व्यापारी आरसी जैन भी शामिल है। इसके साथ ही पेट्रोल पंप व्यवसायी गोलू पहाड़िया, प्रॉपर्टी ब्रोकर, पंकज गोधा, जहीर शेख, कालू उफ बब्बू टेलर, राजेश शर्मा और अमित मिश्रा भी शामिल हैं। आयकर विभाग की टीम ने इनके घरों, दफ्तर और पेट्रोल पंप पर छापा मारा है।

आयकर विभाग की टीम अभी दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि इनके पास से क्या मिला।

राजगढ़ में चार स्थानों पर सराफा व्यापारियों के यहां इनकम टैक्स रेड- धार जिले के राजगढ़ में गुरुवार को इनकम टैक्स टीम द्वारा चार सराफा व्यापारियों के यहां एक साथ छापा मारा। इस दौरान व्यापारियों के मोबाइल बंद करवाकर पूछताछ की जा रही थी। वहीं दुकानों में मौजूद व्यापारियों के अलावा अन्य किसी को अंदर नहीं आने दिया गया। शटर गिराकर टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

आयकर विभाग की टीम द्वारा सुबह करीब 11

बजे मैन चौपाटी स्थित केसर एवं एसवी ज्वलेर्स पर छापा मारा गया। यहां दुकान मालिक एवं घर के अन्य सदस्यों के मोबाइल बंद करवाकर कैश से संबंधित छानबीन की जा रही थी। चारों स्थानों पर अलग-अलग टीमों द्वारा जांच की जा रही है। जैसे ही दुकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई थी। इस मामले में टीम के अधिकारियों से चर्चा की गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने इन्कार कर दिया। उनका कहना था कि जांच के बाद जानकारी दी जाएगी।

शातिर महिला नकबजनी गिरफ्तार

भोपाल। थाना अयोध्यानगर पुलिस द्वारा शातिर महिला नकबजन को गिरफ्तार कर किया चोरी का सामान जप्त किया। आरोपी महिला से मंदिर से चुराये अष्टधातु के पौराणिक जलधारी सहित लगभग 60 हजार रुपये का का मशरूका किया बरामद किए। आरोपी महिला है आदतन चोर और नशे की आदी जो करती है मंदिरों के पौराणिक एंटीक सामग्री चोरी, जिसे अच्छे दामों पर बेचकर करती है अपने नशे के शौक को पूरा करती है। आरोपी महिला करती थी दिन में रैकी तथा रात में देती है वारदात को अंजाम देती।

संसद में गतिरोध, पक्ष-विपक्ष में बढ़ता जा रहा है टकराव

बाहर विपक्ष का घेरा, अंदर निशिकांत बोले-विपक्ष सरकार गिराने की कर रहा कोशिश

राहुल से पूछा- क्या आप खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर तोड़ने वालों से नहीं मिले

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को 8वां दिन था। इस दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच तीखी बहस हुई। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए कि विपक्ष सरकार गिराने की लगातार कोशिशें कर रहा है। निशिकांत ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप

खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर का विभाजन चाहने वालों से नहीं मिले। निशिकांत ने ये भी बताया कि विपक्षी नेताओं का एक धड़ा पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में देश को मिली तरक्की को गलत साबित करना चाहता है। एक संस्था मीडियापार्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि इंडिया संगठन का काम है कि कैसे संसद की कार्यवाही को रोका जाए। निशिकांत ने कहा कि मैं विपक्ष के नेता से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलिल चौधरी से संबंधों पर 10 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए पैसा नहीं दिया।

गौरव गोगोई बोले- मोदी अब संभल में आग लगाना चाहते हैं

असम से सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि भाजपा झूठ बोल रही है। वे संसद नहीं चलाना चाहते। राहुल गांधी देश में शांति कायम करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने जिस तरीके से मणिपुर में आग लगाई, वैसे ही संभल में आग लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी को संभल जाने से रोका गया। विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और गली-गली में शोर है, मोदी-अडाणी चोर है के नारे लगाए। संसद की पिछली 7 कार्यवाहियों में संभल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों की मांग का मुद्दा और अडाणी मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। विपक्षी सांसदों के साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए।

गलतफहमी में मत रहिए आप लोग, बंटेंगे तो कटेंगे: योगी

बांग्लादेश में दुश्मन कृत्य कर रहे, यहां भी ऐसे लोग हैं...

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। सीएम गुरुवार को अयोध्या पहुंचे और उन्होंने संभल में उपद्रवियों से हमदर्दी जताने वालों पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने यहां रामायण मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि संभल, अयोध्या और बांग्लादेश में हिंसा करने वालों का डीएनए एक ही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा,याद करो 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था। आप लोग गलतफहमी में मत रहिए बंटेंगे तो हर हाल में कटेंगे। संभल में भी यही हुआ था और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति और उनका डीएनए एक ही है।

अगर कोई इस पर विश्वास करता है बांग्लादेश में हो रहा है तो वही तत्व यहां भी आपको सौंपने के इंतजार में हैं। उन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बारे में बात करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास विदेश में संपत्ति है।

उज्जैन में दो पक्ष भिड़े, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश

झड़प में एक की मौत, 9 घायल

लड़की भगाने को लेकर विवाद

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन में दो पक्षों में विवाद हो गया। एक-दूसरे पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। एक युवक की मौत हो गई। 9 लोग घायल हैं। घटना बुधवार सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। इसका वीडियो गुरुवार को सामने आया है। मामला जिले के बड़नगर से 11 किलोमीटर दूर ग्राम लिखोदा का है। विवाद की वजह प्रेम प्रसंग और लड़की को भगाकर ले जाना बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें एक महिला भी है। एसडीओपी एमएस परमार ने बताया, शहजाद नामक युवक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की है। आसिफ की रिपोर्ट पर आबिद सहित 10 लोग और दूसरे पक्ष के सद्दाम की रिपोर्ट पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में हत्या, प्राण घातक हमला, बलवा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। घायल आबिद, अफसाना, अल्ताफ, रहीम, आसिफ, रईस,नाहरू, रूस्तम सहित 9 घायलों का उपचार चल रहा है।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मास्को में वीटीबी रूस कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम में

पीएम मोदी की 'इंडिया-फर्स्ट नीति और मेक इन इंडिया' पहल की प्रशंसा की

- राष्ट्रपति पुतिन ने भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की रूस की इच्छा से अवगत कराया
- राष्ट्रपति पुतिन ने एसएमई के विकास के लिए रूस-भारत सहयोग पर जोर दिया

मास्को (एजेंसी)। राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने 15वें वीटीबी रूस कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'इंडिया फर्स्ट नीति और 'मेक इन इंडिया' पहल की प्रशंसा की। राष्ट्रपति श्री पुतिन ने विकास के लिए स्थिर माहौल को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इन नीतियों ने भारत के विकास में किस तरह योगदान दिया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति श्री पुतिन की टिप्पणियों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति को चिन्हित किया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के लिए 'स्थिर स्थिति' बनाने को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई आर्थिक पहलों पर प्रकाश डाला, जिसमें 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया।

राष्ट्रपति श्री पुतिन ने रूस के आयात घटाने के कार्यक्रम और भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के बीच समानताएं बताते हुए भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के प्रति रूस की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश लाभदायक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के नेतृत्व ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित किया है।

रूसी राष्ट्रपति ने कहा, प्रधानमंत्री श्री मोदी के पास 'मेक इन इंडिया' नामक एक ऐसा ही कार्यक्रम है। हम भी भारत में अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार 'इंडिया फर्स्ट' की नीति से प्रेरित होकर स्थिर स्थितियां बना रही है। हमारा मानना है कि भारत में निवेश करना लाभदायक है। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी कंपनी रोसनेफ्ट ने हाल ही में भारत में 20 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

राष्ट्रपति श्री पुतिन ने ब्रिक्स के उदय के संदर्भ में रूस के आयात घटाने के कार्यक्रम के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसमें एसएमई के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा ब्रिक्स व अन्य देशों में एसएमई के लिए सुचारू व्यापारिक लेनदेन की सुविधा के लिए त्वरित विवाद समाधान प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया गया।

उन्होंने बाजार से बाहर हो चुके पश्चिमी ब्रांडों के स्थान पर नए रूसी ब्रांडों के उदय की ओर इशारा किया तथा उपभोक्ता वस्तुओं, आईटी, उच्च तकनीक और कृषि जैसे क्षेत्रों में स्थानीय रूसी निर्माताओं की सफलता के बारे में बताया।

उन्होंने कहा, हमारे लिए, यह हमारे आयात घटाने के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नए रूसी ब्रांडों के उभरने से उन पश्चिमी कंपनियों की जगह लेने में मदद मिल रही है, जो स्वेच्छा से हमारे बाजार को छोड़ चुकी हैं। हमारे स्थानीय निर्माताओं ने न केवल उपभोक्ता वस्तुओं में बल्कि आईटी और उच्च तकनीक वाले उद्योगों में भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

राष्ट्रपति श्री पुतिन ने एसएमई के विकास को समर्थन देने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच और अधिक सहयोग का भी आग्रह किया। उन्होंने सदस्य देशों को अगले साल ब्राजील में होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान सहयोग कायम करने की दिशा में प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। रूस द्वारा ब्रिक्स के साथ मिलकर विकसित किए जा रहे निवेश मंच के बारे में चर्चा करते हुए राष्ट्रपति श्री पुतिन ने कहा कि इसमें सभी भागीदार देशों को लाभ पहुंचाने की क्षमता है और उम्मीद है कि यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने और वैश्विक दक्षिण और पूर्व के देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन जाएगा।

उन्होंने कहा, मैं अपने ब्रिक्स के भागीदार देशों से सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने का आग्रह करता हूं, और हम निश्चित रूप से इसे अपने ब्राजीलियाई नेताओं के ध्यान में लाएंगे, जो अगले वर्ष ब्रिक्स का नेतृत्व करेंगे।

इंदौर में कांग्रेस की संगठन बैठक में जूते-चप्पल चले

निगम के नेता प्रतिपक्ष ने यूथ कांग्रेस के शहर प्रभारी के सीने पर लात मारी

इंदौर (नप्र)। इंदौर शहर कांग्रेस की संगठन बैठक में नेताओं के दो गुटों के बीच जूते-चप्पल चल गए। गुरुवार को गांधी भवन में बैठक बुलाई गई। प्रभारियों के सामने ही इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और आईटी सेल यूथ कांग्रेस शहर प्रभारी दीपक सोनवाने में विवाद हो गया। सोनवाने और उनके साथी बसंत पाटिल को चोट आई है। दोनों ने पंढरीनाथ थाने में शिकायत की है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, निगम में नेता प्रतिपक्ष चौकसे जब बैठक में भाषण दे रहे थे, तभी कांग्रेस कार्यकर्ता बसंत पाटिल बीच में बोल पड़े कि यह तो बीजेपी से मिले हुए हैं। हर महीने बंधा हुआ पैसा निगम से इन्हें मिलता है, यह क्या करेंगे। सोनवाने ने भी पाटिल की बात का समर्थन किया। इसी बात पर चौकसे और उनके समर्थक नाराज हो गए। कहासुनी मारपीट में बदल गई। यह देख प्रभारी और शहरा अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा सभी दाएं-बाएं हो गए।

मेरा टिकट कटवाया, खुद रिकॉर्ड मतों से हारे- घटना पर दीपक सोनवाने ने कहा- इंदौर विधानसभा-2 की संगठन बैठक चल रही थी। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। उन्होंने (चिंटू चौकसे) मुझसे पुरानी खुन्नस निकाली है। इन्होंने मेरा टिकट कटवाया था। चिंटू ने मेरी पसली में जूता मारा और लात मारी है। विधानसभा में यह 1.07 लाख रिकॉर्ड मतों से हारे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कुछ बोलो तो धमकियां मिलती हैं कि घर से उठवा लेंगे या जान से मरवा देंगे। जब चौकसे से एक कार्यकर्ता के सिर में चोट के बारे में पूछा गया तो वे बोले कि प्लास्टिक की कुर्सी से लग गई और मुस्कुरा दिए।

थाने पहुंचा विवाद- पंढरीनाथ टीआई कपिल शर्मा ने बताया, दोनों पक्षों के कार्यकर्ता थाने आए थे। एक पक्ष से दीपक और दूसरे पक्ष से संदीप चोट आई है। मेडिकल कराया है। दोनों पक्षों के नेता समझौते की बात कह रहे थे। अगर शिकायत आती है, तो एक्शन लिया जाएगा।

दो दिन हो रही बैठक- कांग्रेस की यह बैठक 5 और 6 दिसंबर को हो रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व मध्यप्रदेश के सहप्रभारी संजय दत्त, शहर प्रभारी रवि जोशी, जिला प्रभारी अवनीश भार्गव, सह प्रभारी सोमिल नाहटा, गजेंद्र सिसोदिया और तरुण बाहेती इसमें शामिल हुए। आज सबसे पहले विधानसभा दो और दोपहर में विधानसभा चार की बैठक हुई। कल बाकी विधानसभा को लेकर बैठक हैं। इसमें शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और संगठन मंत्री शहर कांग्रेस कमेटी महेंद्र सिंह रघुवंशी ने सभी को आने के लिए कहा है।

चौकसे से बोले- यह परिवार का मामला

चिंटू चौकसे का कहना है, यह परिवार का मामला है, कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस में सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन आरोपों में तथ्य होना चाहिए। ऐसे ही कुछ नहीं बोला जाता है। सोनू नाम के एक कार्यकर्ता के सिर में भी चोट आई है। जब चौकसे से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, वो गिर गया, कुर्सी से चोट लगी। जब मीडिया ने फिर पूछा कि प्लास्टिक की कुर्सी से चोट लगी? तो वे मुस्कुरा दिए।

इंदौर मारपीट मामले में यूथ कांग्रेस के नेता निलंबित, बीजेपी बोली-टीम जीतू ने दिग्गी समर्थक का विकेट गिराया

26 नवंबर को इंदौर एयरपोर्ट पर यूथ कांग्रेस के दो गुटों के नेताओं के बीच मारपीट हो गई थी। भले ही दोनों गुटों ने मामला आपस में सुलझा लिया था, लेकिन घटना को संगठन ने गंभीरता से लिया है। यूथ कांग्रेस ने अमित पटेल को निलंबित कर दिया है। अमित, पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े के समर्थक माने जाते हैं। दरअसल, इंदौर एयरपोर्ट पर आए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को शाजापुर में मशाल यात्रा में शामिल होने जाना था। एमपी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह और पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े चिब को अपनी-अपनी कार में बैठाना चाहते थे। चिब, वानखेड़े की कार में बैठे। इसे खुद वानखेड़े चला रहे थे। वानखेड़े दिल्ली से चिब के साथ ही इंदौर आए थे।यूथ कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि प्रोटोकॉल के तहत चिब को अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह की कार में जाना था। इसी बात पर वानखेड़े और सिंह के गुट में विवाद हुआ। देवास कांग्रेस के नेता और एमपी यूथ कांग्रेस में सचिव विश्वजीत सिंह चौहान ने इंदौर के कांग्रेस नेता अमित पटेल के समर्थक को चांटा मार दिया था। इसके बाद पटेल के समर्थकों ने चिब की कार के साथ चल रहे विश्वजीत चौहान के साथ मारपीट कर दी थी।

दोनों गुटों में विवाद की यह वजह

सूत्रों की मानें तो बसंत पाटिल, सोनवाने और फूल सिंह कुवाल, यह सभी विधानसभा दो में साथ में हैं और यह लॉबी चिंटू के खिलाफ है। इसमें कुवाल को पार्षद का टिकट चाहिए था, तो बाकी कार्यकर्ता भी पद और टिकट के लिए आए थे, लेकिन चिंटू के खिलाफ काम करने से यह नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव के पहले एक गार्डन में इस गुट की बैठक भी हुई थी कि चिंटू के साथ काम नहीं करेंगे, बाद में कई लोगों से समझौता हो गया। यह टीम पहले कांग्रेसी और अब बीजेपी में गए मोहन सेंगर के साथ थी। अभी भी सेंगर के कई लोग जो कांग्रेस में ही रह गए हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। चौकसे को लगता है कि एक धड़ा उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, इसके चलते लगातार इन दोनों के बीच में विवाद जारी है।

बीजेपी ने कसा तंज

इंदौर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो मध्यप्रदेश के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया गया है। उधर, कांग्रेस संगठन के एक्शन पर बीजेपी ने चुटकी ली है। एमपी बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक्स पर लिखा-जीतू पटवारी के समर्थक मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष ने दिग्विजय सिंह के समर्थक विपिन वानखेड़े गुट के अमित पटेल का इस पिटाई कांड के बाद विकेट गिराया।

इंदौर के हॉस्टल में मिला इंटीरियर डिजाइनर स्टूडेंट का शव

दोस्त पहुंचा तो बाथरूम के पास बेसुध पड़ी मिली, जांच शुरू

इंदौर (नप्र)। इंदौर के लसूड़िया इलाके की एक हॉस्टल में गुरुवार सुबह युवती का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एमवाय भेजा है। मामले की जांच की जा रही है। लसूड़िया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, कशिश (22) पुत्री के एम वाधवानी निवाली ग्वालियर का शव इलाके के एक निजी हॉस्टल में कमरे में बाथरुम के पास पड़ा मिला है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। यहां से शव को एमवाय भेजा गया है। कशिश इंटीरियर डिजाइनर की पढ़ाई कर रही थी। टीआई तारेश सोनी के मुताबिक, कशिश के पिता रिटायर्ड बैंक अधिकारी है। वह कल से किसी का फोन नही उठा रही थी। दोस्त तनिष्क उसे देखने पहुंचा था। तब कशिश का शव बाथरुम के पास पड़ा मिला। मृतका मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली है। मामले में जांच की जा रही है।

चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर पर केस

10 माह तक रुपए जमा करने पर 40 प्रतिशत प्रॉफिट का लालच देकर कंपनी भागी

इंदौर (नप्र)। इंदौर में 10 माह तक रुपए जमा करने के बाद 40 प्रतिशत का प्रॉफिट देने की बात पर चिटफंड कंपनी के मालिक ने धोखाधड़ी की। आरोपी 2014 में कंपनी बंद कर भाग गए थे। महाराष्ट्र में रहने वाले एक शिकायतकर्ता ने इंदौर आने के बाद इसकी शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में चिटफंड कंपनी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। विजयनगर पुलिस ने बताया कि देवकुमार पुत्र अरविंद कुमार राय, निवासी अंविता नगर की शिकायत पर पुलिस ने चिटफंड कंपनी जीएनडी (इंडिया) लिमि. के ऑफिस नंबर 10-12, सेकंड फ्लोर, मेट्रो टावर, मंगल सिटी माल के पास स्थित डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है। देवकुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि वह इंदौर के रहने वाले हैं और वर्तमान में पुणे में रहते हैं। हाल ही में जब वह इंदौर आए, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने इस कंपनी में एफडी कराई थी। जब वह ऑफिस पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उक्त कंपनी 2014 में यहां से चली गई थी।

40 प्रतिशत फायदा पहुंचाने का दिया था लालच- देवकुमार ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर ने उन्हें बताया था कि 5800 रुपए प्रति माह से 10 माह तक रुपए जमा कराए जाएं, जिसके बदले एक साल बाद 40 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। वह कुछ समय बाद पुणे चले गए। इसी बीच कंपनी बंद हो गई। देवकुमार ने इस मामले में वरिष्ठ अफसरों को शिकायत की, जिसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देवकुमार के मुताबिक कंपनी ने उन्हें रसीदें और अन्य दस्तावेज भी दिए थे, जो उन्होंने पुलिस को जांच के लिए सौंपे हैं।

इंदौर में जीण माता मंदिर का वार्षिकोत्सव 12 जनवरी को

पुष्प बंगला सजेगा, मंगल पाठ होगा, माता को अर्पित करेंगे 108 मीटर की चुनरी और गजरा

इंदौर (नप्र)। जीण माता मंदिर स्थापना का वार्षिक उत्सव इस नववर्ष में 12 जनवरी को दोपहर 2 बजे मीरा गार्डन में मनाया जाएगा। इस अवसर पर कुलदेवी जीण माता के भक्तों द्वारा दो क्विंटल रंग-बिरंगे फूलों से 500 वर्ग फीट पर पुष्प बंगला बनाया जाएगा। श्री जीण धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन खंडेलवाल ने बताया कि पुष्प बंगला में गुलाब, मोगरा, जूही व अन्य फूलों का उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में गुजरात की वर्षा सोनी द्वारा मंगलपाठ एवं भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। विशेष रूप से 108 मीटर की चुनरी एवं गजरा जीण माता को अर्पित किया जाएगा। आकर्षक विद्युत सज्जा एवं 101 दीपों की महाआरती भी होगी। माता के भक्त परंपरागत परिधान में यानी पुरुष कुर्ता-पाजामा और महिलाएं लाल चुनरी की साड़ी में उपस्थित होंगी।

पूर्व मंत्री ठाकुर बोलीं: इंदौर में बांग्लादेशियों की जांच हो

विधायक मेंदोला ने एक्स पर लिखा- यूनुस से वापस लिया जाए नोबेल शांति पुरस्कार

इंदौर (नप्र)। इंदौर में रह कर काम कर रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अब बीजेपी की पूर्व मंत्री भी मैदान में आ गई है। मंत्री ने प्रशासन से इंदौर के सराफा बाजार और सदर बाजार में रहकर काम कर रहे बांग्लादेशियों की जांच कर उन्हें तत्काल यहां से विदा करने की मांग की है। बता दें कि पिछले दिनों इंदौर कांग्रेस ने भी शहर में रह रहे बांग्लादेशियों की जांच की मांग की थी। कांग्रेस ने सराफा एसोसिएशन को पत्र लिखकर जांच करने को कहा था। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनैतिक तरीके से यहां रह रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मंत्री व महू विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि, हम जिला प्रशासन को पत्र लिखकर यह मांग कर रहे है कि जितने भी बांग्लादेशी कारोबारी और मजदूर यहां काम करने आए है इनका भी परिक्षण किया जाना चाहिए। इनका आधार कार्ड और समग्र आईडी चेक करना चाहिए। वहीं जितने भी बांग्लादेशी है उन सबको यहां से तत्काल विदा करना चाहिए। गौरतलब है कि इंदौर के सराफा बाजार में 15,000 से अधिक बंगाली कारीगर सोने के जेवर बनाने का काम करते हैं। ये कारीगर सराफा बाजार के आसपास किराए के मकानों में रहते हैं और सराफा बाजार में दबढ़ेनुमा कमरों में बैठ कर काम करते है। इन कारिगरों की एक

एसोसिएशन भी है। सूत्रों के मुताबिक, इन कारीगरों में कुछ बांग्लादेश से आए लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी सही संख्या का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है।

विधायक मेंदोला ने नोबल पुरस्कार समिति से की मांग- इंदौर 2 के विधायक रमेंश मेंदोला ने बांग्लादेश में निर्दोष हिन्दुओं के नरसंहार के विरोध में नोबल पुरस्कार समिति से मांग की है कि, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख युनुस मोहम्मद से नोबल विश्व शान्ति पुरस्कार वापस लिया जाए। मेंदोला ने एक्स पर भी पोस्ट करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में हिन्दुओं के नरसंहार और उत्पीड़न के विरुद्ध इंदौर से उठी आवाज अब वैश्विक स्वर ले रही है। मैं नोर्वे स्थित नोबल पुरस्कार समिति से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख युनुस मोहम्मद से नोबल विश्व शान्ति पुरस्कार वापस लेने की मांग करता हूं। बता दें कि युनुस मोहम्मद को नोबल प्राइज कमेटी ने साल 2006 में नोबल विश्व शान्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। नोबल प्राइज कमेटी से मांग करते हुए मेंदोला ने कहा कि-पुरस्कार की नीति की समीक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने देश का मुखिया रहते हुए हिंदू उत्पीड़न, अवैध धर्मांतरण और नरसंहार का जिम्मेदार है। वह नोबल विश्व शान्ति पुरस्कार विजेता कहलाने के योग्य नहीं हो सकता। इंदौर में संघ की आक्रोश रैली को इंदौर बंगाली कारीगर एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया था।

बंगाली कारीगर एसोसिएशन बोला- अगर कोई बांग्लादेशी तो हमें कैसे पता चलेगा- बंगाली कारीगर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशांत सामवंत ने कहा कि, सराफा बाजार में काम करने वाले कारीगर पश्चिम बंगाल से आए हैं, जो भारत का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि इंदौर सराफा बाजार में लगभग 15 से 20 हजार बंगाली कारीगर काम कर रहे है। वहीं उनकी एसोसिएशन में 10,000 से अधिक कारीगर रजिस्टर्ड हैं। यदि कोई बांग्लादेशी नागरिक बंगाली बनकर काम कर रहा है, तो इसकी जानकारी पुलिस को ही जांच कर पता लगानी चाहिए। बता दें कि कल इंदौर में हुए बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन में इंदौर बंगाली कारीगर एसोसिशन ने भी हिस्सा लिया था।

इंदौर के कॉटन कारोबारी के यहां इनकम टैक्स की रेड

इंदौर (नप्र)। मध्यप्रदेश के इंदौर और धार में आयकर विभाग ने कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। विभाग की अलग-अलग टीम इंदौर, देपालपुर और मनावर में सर्चिंग कर रही हैं। जिन लोगों के यहां ये कार्रवाई हो रही हैं उनमें इंदौर के कॉटन कारोबारी और मनावर के बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी, कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी ब्रोकर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गुजरात के किसी रियल स्टेट कारोबारी के हवाला कारोबार में बिटकॉइन में लेन-देन के तार इंदौर और धार के मनावर से जुड़े हैं। छापेमारी के लिए अहमदाबाद और भोपाल से आई अफसरों की टीमें देवास में ठहरी थी। गुरुवार सुबह कार्रवाई शुरू की। धार के मनावर में 70 से अधिक कर्मचारी करीब 30 वाहनों से मनावर पहुंचे। जहां-जहां कार्रवाई चल रही हैं, वहां भारी पुलिसबल तैनात है। इंदौर में कॉटन कारोबारी के तीन ठिकानों पर जांच चल रही है।

घर-ऑफिस में जांच- इंदौर के कालानी नगर स्थित कॉटन कारोबारी सुरेश मेहता के निवास पर टीम ने सर्चिंग शुरू की है। यहां स्थानीय पुलिस की भी मदद ली गई है। इनकम टैक्स की एक टीम जंजीर वाला चौराहा स्थित डीएम टावर में सुरेश मेहता के ऑफिस भी पहुंची थी जो बंद मिला था। कालानी नगर में मेहता का घर और ऑफिस दोनों है। टीम मेहता के घर पर दस्तावेजों की छानबीन कर रही हैं। मेहता के देपालपुर स्थित वेयर हाउस पर भी एक टीम के पहुंचने की सूचना है।इंदौर में मेहता के कालानी नगर स्थित घर में इनकम टैक्स विभाग की टीम छानबीन कर रही हैं।

शादी समारोह में युवक की चाकू घोप कर हत्या

इंदौर में नाचने के दौरान हुआ था विवाद; दोस्त की शादी में दुधिया से आया था

इंदौर (नप्र)। इंदौर के तेजाजी नगर इलाके में बुधवार देर रात एक शादी समारोह में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हमलावर की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक युवक का डीजे वाले से नाचने की बात पर विवाद हुआ था। टीआई देवेन्द्र मरकाम के मुताबिक, घटना ग्वाला कॉलोनी की है। यहां एक शादी समारोह में देव उर्फ विनोद(19) पुत्र घनश्याम रावत निवासी दूधिया की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। रात करीब 1 बजे उसे गंभीर हालत में एमवाय लेकर दोस्त नरेन्द्र और सचिन पहुंचे थे। मृतक देव अपने दोस्त अजय की शादी में आया हुआ था। यहां नाचने की बात पर उनकी डीजे वाले से कहासुनी हुई थी। जिसके बाद विवाद हुआ।

इस दौरान देव और नरेंद्र से मारपीट हुई। तब लोगों ने समझा कर विवाद को शांत किया था। फिलहाल मामले में चिंटू, चेतन, और अखिलेश नाम के युवकों के नाम सामने आए है। इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डीसीपी विनोद मीणा के मुताबिक विशेष नाम के लड़के ने देव को चाकू मारा था। जिससे उसकी मौत हुई है। पुलिस ने डीजे की गाडी भी जब्त की है।

आधे घंटे बाद मिला घायल- दोस्त नरेन्द्र ने बताया कि देव आधे घंटे बाद दोस्त शुभम को शादी वाले जगह से करीब तीन सौ मीटर दूरी पर घायल मिला था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे।

साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को

संपत्तिकर और जलकर के अधिभार में मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट

इंदौर (नप्र)। इंदौर में इस साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को आयोजित होगी। इसे नगर निगम के 22 झोनल ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस और निगम मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। इस लोक अदालत में संपत्ति कर और जलकर के अधिभार पर 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त शिवम वर्मा और राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 के तहत राज्य शासन के निर्देशानुसार, निगम के सभी झोनल ऑफिस और मुख्यालय पर करदाताओं को निम्नलिखित शर्तों पर छूट दी जाएगी।

बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था- लोक अदालत में बुजुर्गों और महिलाओं की सुविधा के लिए विशेष काउंटर और बैठक व्यवस्था की

जाएगी। करदाताओं को संपत्ति कर और जलकर की देय राशि की जानकारी देने और बिल प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है।

बड़े बकायादारों से करेंगे संपर्क- महापौर और निगम आयुक्त ने सभी संपत्ति करदाताओं और जलकरदाताओं से अपील की है कि वे 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत में आकर अपने बकाया कर जमा करें और अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि यह वर्ष 2024 की आखिरी लोक अदालत है। अधिभार की छूट प्राप्त कर राजस्व राशि जमा कराने के लिए सभी झोनों के प्र.सहा. राजस्व अधिकारियों और उनके अधीनस्थ वसूली अमले को निर्देश दिए गए हैं।

इंदौर में 50 हजार में बिक रहा 5 हजार का टिकट

सिंगर दिलजीत दोसांझ के कनसर्ट में टिकट की कालाबाजारी का आरोप

इंदौर (नप्र)। इंदौर में 8 दिसंबर को विख्यात पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का लाइव कनसर्ट होने वाला है। इस कार्यक्रम के टिकट की कालाबाजारी करने के आरोप लग रहे हैं। इंदौर-2 से विधायक रमेश मेंदोला ने टिकट की कालाबाजारी का विरोध करते हुए सिख समाज को उचित राशि पर टिकट उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि पंजाबी सिंगर और फेमस एक्टर दिलजीत दोसांझ भारत में 'दिल-लुमिनाती टूर' कर रहे हैं। इसका एक शो इंदौर में होने वाला है।

सिख समाज और विधायक मेंदोला ने ज्ञापन में कलेक्टर से की मांग- विश्व विख्यात पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का लाइव कनसर्ट कार्यक्रम पहली बार इंदौर महानगर में हो रहा है। सिख समाज में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। कुछ दिन पहले इस कार्यक्रम के टिकट कि ऑनलाइन बिक्री चालू कि गई और कुछ ही मिनट में बिक्री बंद भी हो गई। इस कार्यक्रम के टिकट की मोटी काला बाजारी करने का

मामला सामने आया है। दूसरे शहरों से लोग शहर की होटलों में आकर रुके हैं गए हैं और मोटे दामों पर सौदेबाजी कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इंदौर का सिख समाज भी इस कार्यक्रम का साक्षी बनना चाहता है। आयोजकों द्वारा तय टिकट की कीमत पर ही खरीदना चाहता है। लेकिन काला बाजारियों ने सिख समाज के उत्साह को ठेस पहुंचाई हैं।

विधायक मेंदोला बोले- आयोजन स्थल छोटा, जनता को होगी परेशानी- मेंदोला ने कहा कि मैं सिख समाज के साथ कलेक्टर से मिलने आया हूं। यहां पर संगीत आयोजन का स्थल बहुत छोटा है। वहां की सड़क काफी संकरी है जिसके कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति होने से हमारा पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा। इस आयोजन के टिकट की काला बाजारी हो रही है। 5 हजार के टिकट 50-50 हजार रुपए में बिक रहा है। कार्यक्रम में शराब परोसने की परमिशन भी दी गई है। कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि शराब की परमिशन नहीं दी जाए। वहीं लोगों को 5 हजार का टिकट 5 हजार में ही मिले, ऐसी व्यवस्था प्रशासन करें। इसके लिए हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।

नियमानुसार ही अनुमति दी जाएगी-कलेक्टर

कलेक्टर आशीष सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि सिख समाज के द्वारा इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम को लेकर ज्ञापन दिया गया है। जिसमें ट्रैफिक,टिकट के साथ ही अन्य कुछ चीजों के बारे में लिखा है। नियमानुसार जो भी होगा उसकी अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम में आबकारी नियमों का पालन भी कराया जाएगा। प्रशासन इस बात का भी पूरा ध्यान रखेगा कि कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक की हालत ना बिगड़े।

टिकट काला बाजारी को लेकर लॉ-स्टूडेंट फैन ने भेजा था नोटिस

दिलजीत दोसांझ देश भर के 10 बड़े शहरों में कनसर्ट कर रहे हैं। इस टूर को दिल-लुमिनाती नाम दिया गया है। इस कनसर्ट का सबसे बड़ा शो दिल्ली में आयोजित किया गया था। मगर उक्त कनसर्ट के टिकट के रेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। बता दें कि दिलजीत का उक्त शो कुछ घंटों में ही फुल हो गया था। ऐसे में एकदम से आए टिकट के रेट में उछाल को लेकर दिलजीत की फैन रिद्धिमा कपूर ने उन्हें लीगल नोटिस भेज था।

संपादकीय

असम : गोमांस पर पूर्ण रोक के मायने

गोमाता अब देश की राजनीति के फिर केन्द्र में आ गई है। कभी कांग्रेस से भाजपा में आए और पूर्वोत्तर में कट्टर हिंदुत्व के प्रतीक बन चुके असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अब एक नया दांव चला है। उन्होंने बुधवार को पत्रकारवार्ता कर राज्य भर के होटलों, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। जाहिर है कि इससे पूर्वोत्तर राज्यों में धार्मिक ध्रुवीकरण और तेज होगा। सरमा ने कहा कि नए नियमों को शामिल करने के लिए गोमांस की खपत पर मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। इसके तहत असम में, हमने फैसला किया है कि किसी भी रेस्तरां या होटल में और किसी भी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थान पर गोमांस नहीं परोसा जाएगा। इसके पहले असम में मंदिरों के 5 किमी के दायरे में गोमांस परोसने या सेवन न करने का प्रावधान था। नए आदेश में इसका विस्तार पूरे राज्य में कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि नए आदेश से मुख्य रूप से मुस्लिम, ईसाई और वे अन्य समुदाय जो गाय को केवल एक जानवर मानते हैं, प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ इस आदेश से कट्टर हिंदू खुश होंगे। क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के पहले वहां की महायुति सरकार ने गाय को 'राजमाता' का दर्जा दे दिया था। माना जा रहा है कि विस चुनाव नतीजे महायुति के पक्ष में आने के पीछे यह भी एक कारण रहा है। दरअसल हिमंत बिस्वा के इस फैसले के पीछे तात्कालिक राजनीतिक कारण भी है। हाल में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने सामागुरी के मुस्लिम बहुल इलाके में चुनाव जीतने के लिए गोमांस बांटा था। इस आरोप के बाद भाजपा रक्षात्मक मुद्रा में दिखी। उसने बयानों के जरिए तमाम सफाइयां भी दीं। क्योंकि अभी तक चुनाव में शराब बांटने के आरोप तो लगते रहे हैं लेकिन गोमांस बांटने का आरोप पहली बार लगा था। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि अगर राज्य कांग्रेस प्रमुख भूपेन कुमार बोरा पत्र लिखकर मांग करें तो वह असम में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। यानी सरमा ने बीफ पर अब जो बैन लगाया है, परोक्ष रूप से उसके लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। गौरतलब है कि असम में गोमांस का सेवन अवैध नहीं है, लेकिन असम पशु संरक्षण अधिनियम 2021 उन क्षेत्रों में पशु वध और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक रहते हैं। वैसे भी उत्तर पूर्व (नॉर्थ ईस्ट) राज्यों में गोमांस बड़े पैमाने पर खाया जाता है। नागालैंड, मणिपुर आदि में कई जगह गोमांस मुख्य भोजन में शामिल रहता है। हालांकि आर्यों के आरंभिक काल में भी गाय की बलि देने की प्रथा थी। लेकिन बाद में आर्यों ने गाय को पवित्र पशु का दर्जा दिया गया। इसका आर्थिक कारण भी था। क्योंकि गाय आर्यों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार थी। इसे धार्मिक पवित्रता से जोड़ने से गाय को हिंदू समाज में अलग प्रतिष्ठा और मिली। गाय श्रद्धा का केन्द्र बन गई और आज भी है। लगभग सभी हिंदू गाय को पवित्र प्राणी और सांसारिक वैतरणी को पार कराने का माध्यम मानते हैं। हालांकि गोमांस पर प्रतिबंध और भारत में मांसाहारियों की संख्या पर हमेशा विवाद रहा है। पियू रिसर्च में कहा गया है कि भारत में सिर्फ 39 फीसदी लोग शाकाहार यानी वेजिटेरियन हैं।

नजरिया

सुरेश भाई

लेखक 'उत्तराखण्ड सर्वोदय मंडल' के अध्यक्ष हैं।

गंगाजल के प्रदूषण से मुक्ति के सवाल

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 'गंगा एक्शन प्लान' और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'नमामि गंगे परियोजना' में गंगा की निर्मलता के लिए पर्याप्त बजट, तकनीक, मानव-संसाधन आदि का उपयोग करने के बाद भी गंगोत्री में प्रतिदिन दस लाख लीटर क्षमता वाले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से एकत्रित किए गए नमूने के आधार पर 100 एमएल पानी में 'फीकल कॉलीफॉर्म' का स्तर 540 पाया गया है। फीकल कॉलीफॉर्म का यह स्तर मनुष्यों और जानवरों के मल-मूत्र से निकलने वाले सूक्ष्म जीवों से होने वाले प्रदूषण को दर्शाता है। 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' के अनुसार स्नान और आचमन करने योग्य जल की गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार 100 एमएल पानी में फीकल कॉलीफॉर्म का लेवल 500 से कम होना चाहिए, लेकिन गंगोत्री में ही यह 540 पाया गया है, जो इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जल पीने लायक भी नहीं है। 5 नवंबर 2024 को 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे इसकी निगरानी करके 13 फरवरी 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

गंगा करोड़ों लोगों की आस्था है। देश-विदेश में रहने वाले अनेक हिन्दुओं की जीवन में एक बार इच्छा रहती है कि वे गंगोत्री का साक्षात दर्शन करके गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर पुण्य कमा लें। ऐसे भी बहुत से बुजुर्ग हैं जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर गंगा के दर्शन के बाद मुक्ति की कामना करते हैं, लेकिन पर्यावरण में आ रहे बदलाव के बाद भागीरथी के रूप में गंगोत्री से आ रही गंगा की यह मुख्यधारा उद्गम से ही प्रदूषित हो रही है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 'गंगा एक्शन प्लान' और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'नमामि गंगे परियोजना' में गंगा की निर्मलता के लिए पर्याप्त बजट, तकनीक, मानव-संसाधन आदि का उपयोग करने के बाद भी गंगोत्री में प्रतिदिन दस लाख लीटर क्षमता वाले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से एकत्रित किए गए नमूने के आधार पर 100 एमएल पानी में 'फीकल कॉलीफॉर्म' का स्तर 540 पाया गया है। फीकल कॉलीफॉर्म का यह स्तर मनुष्यों और जानवरों के मल-मूत्र से निकलने वाले सूक्ष्म जीवों से होने वाले प्रदूषण को दर्शाता है।

'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' के अनुसार स्नान और आचमन करने योग्य जल की गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार 100 एमएल पानी में फीकल कॉलीफॉर्म का लेवल 500 से कम होना चाहिए, लेकिन गंगोत्री में ही यह 540 पाया गया है, जो इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जल पीने लायक भी नहीं है। 5 नवंबर 2024 को 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे इसकी निगरानी करके 13 फरवरी 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

चिंताजनक है कि गंगा के उद्गम उत्तराखंड में ही देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, हरिद्वार, टिहरी में लगाए गए लगभग 53 'सीवर ट्रीटमेंट प्लांट' (एसटीपी) की क्षमता अभी इतनी कम है कि वे पूरी तरह गंगा में गिर रहे सीवर की सफाई नहीं कर पा रहे हैं। 25 सितंबर 2024 को 'एनजीटी' ने गंगा - यमुना में प्रदूषण पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। उस दौरान भी कहा गया था कि गंगा का पानी आचमन करने योग्य नहीं है। उत्तरप्रदेश में भी 'गंगा' प्रदूषण की बीमारी से ग्रस्त है। जहां पर 22 अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट में 326 नालों में से 247 नाले बिना शोधित है। जिसमें से 3513.16 एमएलडी सीवेज गंगा और सहायक नदियों में गिर रहा है।

6 नवंबर 2024 के आदेश में 'एनजीटी' के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि प्रयागराज जिले में सीवेज शोधन में 128 एमएलडी

का अंतर है। इसके अलावा यहां के 25 नालों से गंगा में बिना शोधित सीवेज गिर रहा है और यमुना में भी 15 नालों से बिना शोधित सीवेज जा रहा है जिसके कारण मैदानी क्षेत्रों में कहीं भी गंगा जल की गुणवत्ता नहीं बची है।

गोमती नदी में रासायनिक प्रदूषकों के बढ़ने से भी मछलियों की मौत हो रही है। इसमें कम पानी होने के कारण अधिक प्रदूषणकारी तत्व गोमती में जमा हो गये हैं। यही हालात गंगा की सहायक काली, हिंडन, रामगंगा, तमसा, बेतवा, असी, वरुणा समेत डेढ़ दर्जन नदियों की भी है जहां ये नदियां पहले ही नाले का रूप ले चुकी हैं। उत्तरप्रदेश के 23 जिले जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, इनमें से 12 जिलों में तो पानी को साफ करने की सुविधा अभी तक मौजूद नहीं है, जबकि वाराणसी, फर्रुखाबाद, कानपुर, उन्नाव और मिर्जापुर जिलों से गंगा में आ रहे गंदे नालों की ताज़ा स्थिति उपलब्ध होनी बाकी है।

दिल्ली में यमुना की तरह गंगा के पानी में भी जगह-जगह सफेद झाग दिखाई दे रहे हैं। पटना में ऐसे ही 507 नाले चिन्हित किए गए हैं, जो बिना ट्रीटमेंट के ही गंगा में गिर रहे हैं। प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कि यहां दीघा नहर का जहरीला रसायनयुक्त काला पानी बेधड़क गंगा में पहुंच रहा है जो मनुष्य और पशुओं की सेहत बिगाड़ रहा है। पेयजल के लिए इस्तेमाल हो रहे भूमिगत पानी में पहले से ही खतरनाक रसायन घुले हुये हैं। अभी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इसी पानी में 4-5 लाख लोगों ने स्नान किया है, जबकि यहां फीकल कॉलीफॉर्म नामक खतरनाक जीवाणुओं की संख्या मानक से कई गुना अधिक है।

जल वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार गंगाजल में 'बैट्रींयोफोस' नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो जल के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है जिससे गंगाजल की शुद्धता अपने आप ही बनी रहती है, लेकिन अंधाधुंध प्रदूषण के कारण इस तरह के लाभदायक बैक्टीरिया भी उद्गम से ही समाप्त हो रहे हैं। पूर्व मंत्री उमा भारती के बाद 'जल संसाधन मंत्रालय' की कमान जब 'सड़क एवं राजमार्ग मंत्री' नितिन गडकरी को सौंपी गयी थी, उन्होंने 2017 तक गंगा को निर्मल करने का आश्वासन दिया था।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गंगा की निर्मलता, अविरलता के लिए 2014 में निर्धारित 20 हजार करोड़ की राशि के अलावा अधिक आवश्यक होता कि सरकार और समाज मिलकर प्रदूषणकारी तत्वों को, जो पूरी तरह मानव-जनित हैं, विभिन्न संवादों और नियमों के आधार पर रोके जाते। इसके लिए गांव की जल एवं स्वच्छता समिति से लेकर राज्य और केंद्र के संबंधित मंत्रालय मिलकर प्रयास कर सकते थे।

गंगा की सफाई के नाम पर दो प्रयास अधिक प्रकाश में आए हैं जिसमें पहला स्नान घाटों की सफाई, जहां पर रंग-बिरंगे टाइल लगे हुए हैं। दूसरा 'एसटीपी' के सहारे गंगाजल की सफाई, जबकि बरसात में 'एसटीपी' ध्वस्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि गंदगी करने वाले अनियंत्रित पर्यटकों, उद्योगों, प्लास्टिक संस्कृति को मौका मिल रहा है कि वे अपने उपयोग के बाद पैदा होने वाली गंदगी और मानवीय मल-मूत्र को जहां भी विसर्जित करेंगे वहां जल-शोधन की प्रक्रिया से साफ हो जाएगा। ऐसा न करने से उन्हें कोई रोक भी नहीं रहा है जिसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते गंगाजल को प्रदूषण से मुक्ति कैसे मिलेगी? (सप्रेस)

मुद्दा

आजम खान

लेखक अभिभाषक हैं।

गैस त्रासदी के मानवीय पहलू अनूठे और चौंकाने वाले

2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात, जब भोपाल के आसमान पर जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस का साया छाया, वह इतिहास के सबसे घातक औद्योगिक हादसों में से एक बन गई। इस भयंकर औद्योगिक आपदा का जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड का कीटनाशक प्लांट था, जिससे मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस का रिसाव हुआ। परिणामस्वरुप लगभग 3,500 से अधिक लोग मरे और अनगिनत बीमार और घायल हुए है। जिसके बाद अस्पताल घायलों से, श्मसान मुर्दों से भर गए और हजारों लोग अपने घरों से जान बचाने के लिए आसपास के इलाकों में निकल पड़े। इसके बाद कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर 2,000 डॉलर की जमानत पर रिहा कर दिया जाता है और वे भारत छोड़ देते हैं। असल में यह त्रासदी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लालच, लापरवाही और मानवीय जीवन के प्रति उदासीनता उजागर करती है।

कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी का एक ही मकसद होता है कि अधिक-से-अधिक मुनाफा कमाना। इस लालच में वे औद्योगिक संस्थानों को अमानक तरीकों से चलाना, नियमों और चेतावनियों की अनदेखी करना एक आम बात है। जैसे की आप इस त्रासदी के सन्दर्भ में देखें तो पाते हैं कि यूनियन कार्बाइड ने चेतावनियों पर कभी ध्यान नहीं दिया जो उस समय के दस्तावेज और दैनिक अखबारों देखने से पता चलती हैं। टैंक में मानक सीमा से अधिक मिक रखी गयी, नियमित निरीक्षण और मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया गया जो कि प्रबंधन की लापरवाही को बताता है।

इसके बाद देखें तो पता चलता है कि गैस रिसाव को रोकने वाले उपकरण और अलार्म सिस्टम निष्क्रिय थे और स्थानीय कर्मचारियों को आपात स्थिति से निपटने का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। संयंत्र के आसपास घनी आबादी के बावजूद, लोगों को संभावित खतरों से अनजान रखा गया जो कि प्रशासन और कंपनी का दायित्व था। इन सारी लापरवाहियों को जानने के बाद टैंक में मानक सीमा से अधिक MIC रखना और अनियमित निरीक्षण और मरम्मत को नज़रंदाज़ करना आप को कुछ खास बात नहीं लगेगी।

मानवीय जीवन के प्रति उदासीनता का अंदाज़ा आप 40 साल की राजनैतिक पहलकदमियों, राहत कार्यों और मुआवजे के वितरण को देखकर लगा सकते हैं। बीते सालों में भारत और अमेरिका के बीच कई सरकारें बदलीं और उन्होंने व्यापार, सुरक्षा और संस्कृति जैसे कई विषयों पर द्विपक्षीय समझौते भी किये, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी का मुद्दा कभी भी उनकी प्राथमिकता में नहीं आया। आप ऐसा भी न समझें की सरकारें इसे भूल गईं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हर साल गैस त्रासदी की बरसी के दिन सभा में शामिल होते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और एक मंत्रालय और मंत्री भी है जिनकी अहमियत लगातार कम होती जा रहा है या यूँ कहा जाये उनकी दिलचस्पी भी न के बराबर है। दोनों देशों के बीच इस त्रासदी के संदर्भ में केवल कुछ संवाद ही हुआ, जब पीड़ितों ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर न्याय की मांग की।

उदासीनता का मंजर आप को गैस राहत अदालतों के गठन से भी समझ सकेंगे। शुरुआती दौर में मुआवजे के दावों के लिए शासन ने तक़रीबन 56 अदालतों और 5-7 अपीलीय अदालतों का गठन किया था जो आज केवल एक पर आकर थम गई है। आप समझ सकते हैं कि हजारों मुआवजे के दावों पर इन अदालतों में न्याय की रफ़्तार कैसी रही होगी और एक विधिक विद्यार्थी के तौर पर मैं समझ सकता हूँ कि वहां न्याय और मुआवजे के साथ पीड़ितों और फर्जी पीड़ितों के बीच मुआवजे को पाने की कैसी जंग हुई होगी, जिसका छुटभइये नेता, दलालों और बाबुओं ने कैसा फायदा उठाया होगा। पीड़ितों के लिए बहुत अहम् सेवा, स्वास्थ्य सेवा है, जहां उन्नत चिकित्सा के लिए 'भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर' को स्थापित किया गया। हालांकि, वित्तीय संकट और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण यह अस्पताल अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करने में नाकामयाब रहा है। कई गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को प्राथमिकता नहीं मिल पा रही, और समय पर इलाज न होने से उनकी स्थिति और बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति ने भी इस ओर ध्यान दिलाया कि अस्पताल की सेवाएं अपर्याप्त हैं और धन की कमी इसकी मुख्य वजह है, लेकिन इसकी तकलीफों का अंत नहीं दिखता। इन विशेष स्वास्थ्य सेवाओं और पीड़ितों की हालात देखकर सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा कर सकते हैं कि दोनों में से कौन जल्दी ठीक होगा। साथ ही इस स्वास्थ्य सेवा संस्थान द्वारा गैस पीड़ितों के लिए किये गए अध्ययन और सिफारिशें भी उत्सुकता का विषय हो सकते हैं। अब पीड़ितों को आयुष्मान योजना में भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन वे तभी शामिल हो सकेंगे जब पीड़ित के पास स्मार्ट कार्ड होगा।

आज चार दशक बाद भी स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिति गंभीर बनी हुई है। पीड़ितों और उनके परिवारों पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी असर जारी हैं। जिसमें मुख्यरूप से कैंसर, फेफड़ों और यकृत के रोग, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ व्यापक रूप से दर्ज किए गए हैं। गैस के प्रभाव से जन्म दोष और गर्भपात की दर अधिक है। त्रासदी से बची महिलाओं के बच्चों में भी कई प्रकार के स्वास्थ्य विकार देखे गए हैं, लेकिन इन समस्याओं के बीच एक स्वैच्छिक अस्पताल अपनी सेवाएँ दे रहा है और अध्ययनों में सहायक भी है जो अपने आप में एक मिसाल है।

इसके अलावा, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री स्थल पर छोड़ा गया जहरीला कचरा आज भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है। लगभग 300 मीट्रिक टन से अधिक ठोस और तरल जहरीला कचरा फैक्ट्री परिसर में पड़ा है, जो मिट्टी और भूजल को प्रदूषित कर रहा है। जिससे लगभग 3 लाख लोगों की आबादी प्रभावित है जो दूषित पानी पीने को मजबूर है और जिसके कारण उन्हें जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या का समाधान न होने का मुख्य कारण जिम्मेदारी तय करने में देरी है। त्रासदी के लिए यूनियन कार्बाइड और उसकी मूल कंपनी डॉव केमिकल्स को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उन्होंने जहरीले कचरे के निपटान से पल्ला झाड़ लिया। सरकार और स्थानीय प्रशासन भी समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने में असमर्थ रहे हैं। कानूनी लड़ाई, मुआवजा विवाद और पर्यावरणीय समस्याओं की उपेक्षा ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।

सरकार द्वारा कई बार जहरीले कचरे के निपटान की योजनाएँ बनाई गईं, लेकिन उनमें से अधिकांश अधूरी रह गईं। कई बार प्रस्तावित स्थानों पर स्थानीय विरोध के कारण कचरे को सुरक्षित रूप से हटाया नहीं जा सका। वैज्ञानिक और पर्यावरणविदों का मानना है कि इस कचरे का निपटान अत्यधिक सावधानी और आधुनिक तकनीकों से किया जाना चाहिए ताकि और नुकसान न हो। भोपाल गैस त्रासदी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। यह हमें याद दिलाती है कि विकास और उद्योग के साथ-साथ मानवता और पर्यावरण की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस त्रासदी से सीखी गई शिक्षा को आगे आने वाले खतरों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

वैसे एक विकासशील देश का लोकतान्त्रिक चेहरा ये मिसाल पेश करता हैं, की सरकारें और कंपनी जिसे एक दुर्घटना मानती हैं वंहा पर भी उस दुर्घटना के शिकार लोगों को 40 साल बाद भी न्याय, कॉर्पोरेट जवाबदेही, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए न खत्म होने वाले संघर्ष और भुला दिए जाने तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। भोपाल गैस त्रासदी के संघर्ष के कुछ मानवीय पहलू बेहद चौंकाने वाले हैं, जो शायद आज के भारत के लिए अनूठे हो सकते हैं। जैसे कुछ मशहूर और कई अनजाने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, महिलाओं और समाज विज्ञानियों का योगदान अलग-अलग तरीकों से रहा है। इस संघर्ष को किसी ने सड़क पर, किसी ने न्यायालय में, किसी ने स्वास्थ्य संस्थानों (अस्पताल) में, किसी ने प्रकाशनों में और महिलाओं ने परिवार और समाज में साम्प्रदायिक और सामाजिक सौहार्द्र के साथ जिया और जिंदा रखा है। जिसमें भोपाल के लोग ही नहीं देश और दुनिया के तमाम लोग और संगठन जो न्याय, जन-स्वास्थ्य, पर्यावरण, और मानवाधिकारों के प्रति समर्पित हैं वे आज भी चुनौतियों का सामना करते हुए अलग-अलग मोर्चों पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कार्पोरेटी राक्षस को उसके गुनाह की सजा अहिंसक तरीके से दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। (सप्रेस)

निज-निज रुख रामहि सबु देखा

सीता-राम विवाह प्रसंग

ध्रुव शुक्ल

लेखक साहित्यकार हैं।

रामायण कहती हैं कि राम की कोई उपमा नहीं। राम के समान राम ही हैं। इसके बावजूद भी राम पर विभिन्न सांसारिक और पारमार्थिक दृष्टियां तो पड़ती ही हैं और सब राम को अपनी-अपनी दृष्टि से देखते हैं। कोई राम को निरञ्जन के रूप में और कोई हिन्द के इमाम के रूप में देखता है। सब राम को देखते हैं। राम में रहीम को भी देख लेते हैं।

जब राम सीता स्वयंवर की सभा में शिव धनुष भंजन करने आये तो वहाँ उपस्थित रणधीरों ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वीर रस ही शरीर धारण करके आ गया हो..... महाकवि तुलसीदास कहते हैं... कुटिल राजाओं को राम भयानक मूर्ति की तरह दिखे। जो असुर छलपूर्वक राजाओं के वेष में बैठे थे उन्हें राम विकराल कालरूप ही दीखे। नगरवासियों ने राम को सुखपूर्ण सौन्दर्य के रूप में देखा। विद्वानों को राम विराट रूप दिखायी दिए।

राजा जनक के कुटुम्बियों को राम सगे सम्बन्धी जैसे लगे। जनक समेत सब रानियाँ ममता से भरकर राम को अपने बच्चे के समान ही देख रही थीं। योगियों को वही राम शान्त और स्वयं प्रकाशित भास रहे थे। भक्तों ने उन्हें अपने इष्टदेव की तरह देखा। तुलसीदास कहते हैं कि... सीता जिस भाव से राम को देख रही हैं वे भी उसे नहीं कह सकतीं तो फिर कोई कवि उसे कैसे कहे।

राम ने सीता को पाने की बड़ी तैयारी की थी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टेगोर याद दिलाते हैं कि... जनक, विश्वामित्र और राम भागवत इतिहास में निकटवर्ती हैं। विश्वामित्र ही राम को जनक के घर ले गये। राजा जनक ब्रह्मज्ञानी किसान थे। राम ने विश्वामित्र के साथ चलकर अहिल्या धरती (पड़ती ज़मीन) को सजीव करके खेती के योग्य बनाया। सीता भू-कर्षण जात कन्या हैं, वे पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई हैं। राम चेतन बीज हैं। दोनों की यह पुरातन प्रीति समझते तो बनती है पर बखानी नहीं जाती।

धरती पर आर्द्रता का न होना ही सबसे बड़ा अभाव है। किसान इसी नमी के भरोसे अपने हल की नोंक से खेतों में रेखायें खींचकर मिट्टी की कोमल गहराई में बीज बोते हैं। खेतों में खींची गयी यह रेखा सीता कहलाती है। राम बीज हैं जो सीता में सिमटी हुई आर्द्रता में बोये जाते हैं। प्रकृति में चेतना का आश्रय ही सीता और राम का मिलन है।

स्वयंवर में सीता की व्याकुलता को कोई कैसे जाने। उनका धीरज डोलता है। शिव धनुष के सामने राम की सुकुमारता को देखकर सीता के हिरनी के समान नेत्र विह्वल हैं कि यह धनुष तोड़ने में राम सफल हों। वे लज्जा के कारण अपनी वाणी से कुछ कह नहीं सकतीं। बस उनके नयनों का जल पलकों की कोरों में अटका रह गया है।

राम ने मन ही मन सीता की विकलता को भाँप लिया और बड़े लाघव के साथ धनुष उठा लिया। वह शिव धनुष बिजली की तरह चमका और धरती पर उतरने के पहले मेघों को संभालने वाले आकाश में मण्डलाकार हो गया। कोई जान ही पाया कि वह कब टूटा। धनुष टूटते ही सखियों ने सीता से कहा...अब देर किस बात की। चलो राम को जयमाल पहनाओ। यह सुनकर सीता ने माला तो उठा ली पर न जाने किस प्रेम के विवश होकर वे उसे राम के गले में डाल नहीं पा रहीं। सीता के शरीर में संकोच है और मन में उछाह है। राम और सीता की इस रहस्यमयी पुरातन प्रीति को कोई देख नहीं पा रहा।

राम जीवन जल होकर धरती के हृदय में प्रतिष्ठित हैं। जलहीन धरती के दरके हुए हृदय का दुख राम ही जानते हैं। राम और सीता का प्रेम पृथ्वी पर सरोवरों में सिमट आये जल जैसा है। इस प्रेम की राम कहानी सुनकर सबके नेत्र सजल हो उठते हैं। शरीर पुलकित और वाणी गदगद हो जाती है। प्रकृति में राम रूपी जीवन जल की प्रतिष्ठा ही सीता-राम का पाणिग्रहण है। वे प्रत्येक संवत्सर में अपना ब्याह रचाते हैं।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) - गिरीश उपाध्याय
वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

प्रीतम लखवाल

लेखक व्यंग्यकार है

...बिन इंटरनेट सब सून

रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, श्लेष अलंकार में लिखा संत रहीम का यह दोहा आज कहीं विलुप्त सा हो गया है। वह भी इसलिए कि लोग पानी का मोल आज भी नहीं पहचान पाए। अपव्यय के मामले में हम विश्व में नंबर एक होने का खिताब तो ले ही सकते हैं। वैसे भी पानी अब किसी के पास नहीं है। सब बोतल पर निर्भर हो गए हैं। नेताओं ने पानी को बहुत गहराई से समझा है तभी तो वे पानी की तरह बहते हुए सागर से महासागर में समाते जा रहे हैं। मैं यहां पर बात पानी की नहीं करने वाला, क्योंकि पानी आज बहुत कीमती हो गया है। सस्ता तो बस इंसान का खून ही बचा है। मैं यहां पर बात दूसरी ही कर रहा हूं। हमारे पड़ोसी विकटलाल जी बहुत दिनों से परेशान थे। उन्होंने अपने सेलफोन के कई मॉडल बदल लिए। फिर भी परेशान रहते। एक दिन मिल गए रास्ते में तो अपना सिर खुजाते हुए ही मिले। मैंने उन्हें धीरे से नमस्ते ठोंक दिया। वे बोले- हां-हां ठीक है वो तो...। मैं हैरान था कि यह क्या प्रत्युत्तर मिला मुझे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन्हें कुरेदने की दृष्टि से पूछा- क्या बात है भाई साहब! वे इसी नाम से जाने जाते थे और यह सुनते ही उनमें शक्ति का संचार भी दुगना हो जाता था।

उन्होंने कहा-कुछ नहीं यार कई मोबाइल बदल चुका हूं, मुआ नेटवर्क नहीं मिलता। किसी से बात नहीं हो पाती। न किसी के फोन आते हैं और अपन लगाते हैं तो बस...। फिर कभी नेटवर्क आ जाए तो इंटरनेट नहीं पर्याप्त नहीं मिलता। रिचार्ज करवाकर कंपनी का भला कर रहा हूं, लेकिन इसका एक पैसे का फायदा मुझे नहीं हो रहा है। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि एक बार मोबाइल चेक करा लो। शायद समस्या का समाधान मिल जाए। वैसे भी अपने यहां समस्याओं के समाधान सिस्टम को री-स्टार्ट करने से ही हो जाता है। इंटरनेट क्या बला है। इस इंटरनेट के मामले में सबसे ज्यादा भारतीय गृहणियां परेशान हैं। उनके लिए

इंटरनेट ही सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर जो है।

युवतियां तो उनसे भी आगे हैं। वे पहाड़ों पर भी इंटरनेट ढूंढ लेती हैं, रील बनाने के चक्कर में वहां से जंप भी लगा देती हैं। जब उनका इंटरनेट पैकेज खत्म हो जाता है और मोबाइल बफरिंग करने लगता है तो उनके सिर में दर्द शुरू हो जाता है। यही हाल महिलाओं का होता है। जिस दिन पैकेज खत्म उस दिन घर में केवल खिचड़ी से काम चलाना पड़ता है। दिनभर थक-हारकर पति घर लौटता है तो पत्नी कैकयी की तरह बेडरूम में कोपित होकर लेटी मिलती है। जब पति पूछता है कि क्या हुआ तो कहती है नेट नहीं चल रहा। इस आधुनिक युग में मोबाइल ने क्रांति तो ला दी, लेकिन असल क्रांति तो घरों में आई है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान। सब आजकल इंटरनेट पर ही सवार हैं और बेचारे लिक्खड़, साहित्य मनीषी की कलम नहीं अंगुलियां हरकत नहीं करती हैं। वे भी परेशान रहते हैं। इधर-उधर समारोह में कहते फिरते हैं कि 'फलाने इंटरनेट राखिए इंटरनेट बिन सून, इंटरनेट गए न उबरे...। भाई साहब क्या करें, सब इस पर ही निर्भर हैं। एक बार पॉकेट में रुपए न हो चलेगा, लेकिन अगर मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो न मेल होंगे न वाट्सएप होंगे। इससे सब परेशान हैं। मेल हों या फी-मेल। इसलिए अपन तो अनलिमिटेड पैकेज लेकर चलते हैं। कहीं कोई झंझट ही नहीं।

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। संप्रति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के डॉ. आंबेडकर चेयर में चेयर प्रोफेसर हैं।

अपने जैसे व्यक्ति की खोज में डॉ. आंबेडकर

डॉ. आंबेडकर का महाप्रयाण 6 दिसंबर को हुआ था. उन्हें देश के भारत रत्न के रूप में जाना जाता है. उन्हें विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और वंचितों व शोषितों के मसीहा के रूप में स्मरण किया जाता है. जब देश में वंचितों के बारे में ठीक राय नहीं थी उन दिनों साबित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले सामाजिक न्याय के लिए कार्य कर रहे थे. उनके बाद यदि डॉ. आंबेडकर न होते तो जो वैक्यूम था वह रिक्त रहता लेकिन डॉ. आंबेडकर जिन्होंने स्वीकार किया कि उनके गुरु ज्योतिबा फुले हैं, उनका संघर्ष, समर्पण और त्याग के साथ प्रयास यह बताता है कि उन्होंने अपने गुरू के पदचिन्हों पर चलकर दलितों और शोषितों की वह आवाज़ बने.

जब देश की आबादी 35 करोड़ के आसपास थी. देश में तब रिसोर्सेस बहुत कम थे. सबका जीवन कृषि आधारित था. खेतों-खलिहानों में मजदूरी और श्रम मनुष्य की ताकत थी. उन दिनों धनाड्य समाज, सक्षम समाज दलितों के साथ जो बर्बरता किया उससे डॉ. आंबेडकर बहुत दुखी थे. गरीबों व दलितों का मनमाना शोषण हुआ करता था. सवर्ण समाज तय करता था कि वह किसको भर पेट भोजन देगा, किसको मजदूरी देगा और किसका जीवन किस प्रकार चलेगा. सोचिये की आज़ादी के पहले का समाज किस स्थिति में था. उन दिनों के उस पड़ाव को झेलती हुई शोषितों व वंचितों की आबादी अस्पृश्यता की शिकार थी. छुआछूत बीमारी की तरह समाज में व्याप्त थी. भारत की एक आबादी यह सब झेल रही थी. गाँधी ने भी हरिजनोद्धार के लिए कार्य किये. उनके कार्य करने के तरीके चाहे जो भी हों, लेकिन उन्होंने उन दिनों इस पर कार्य किया लेकिन डॉ. आंबेडकर इसलिए उनकी मुखरित आवाज़ के रूप में स्मरणीय हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही वस्तुस्थिति को करीब से समझा था. वह भारतीय दासत्व से जीवन जी रहे लोगों के बहुत करीब थे.

भारत में सबसे बुरी व्यवस्था यदि कोई औपनिवेशिक काल में थी तो वह थी गरीबों और दलितों के साथ भेदभाव और अस्पृश्यता की समस्या. भारत के सक्षम लोगों ने इनके साथ दासों जैसा व्यवहार किया और उनके मनुष्य होने पर भी सवाल किया. वे हीन भावना से उन्हें देखते थे. उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और नानाप्रकार के शोषण उनके लिए अभिशप्त जीवन जैसा ही था. जब दलित व वंचित के पुरुष इस स्थिति को झेल रहे थे तो स्त्रियों की दशा क्या रही होगी, इसकी कल्पना कर सकते हैं. डॉ. आंबेडकर ने इन समस्याओं को रेखांकित किया और यह समझने की कोशिश की कि इस समस्या की जड़ें कहाँ से हैं और इसे समाप्त करने के लिए संघर्ष कितना ज़रूरी है.

डॉ. आंबेडकर स्वाभिमानी, राष्ट्र में अपने मूल्यों के साथ जीने वाले लोगों में थे. उन्होंने समझौता नहीं किया. वह कभी हार नहीं मानने वाले इंसान थे. 4 फरवरी, 1940 को मझगांव, मुंबई में दुर्घटना से बचने के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का अभिनंदन करने हेतु एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में बोलते हुए डॉ. बाबासाहेब ने कहा कुछ लोग मुझे मानते हैं मैं उसी में संतुष्ट हूँ. सिद्धांतों को त्याग कर मुझे काँग्रेस का नेता, मजदूरों का नेता, किसानों का नेता बनने का कोई शौक नहीं.' कांग्रेस और गाँधी से अपनी नाराजगी वह इसलिए जाहिर करते थे क्योंकि उनके सारे संघर्ष का जो प्रतिफल आने वाला था वह दलितों के पक्ष में नहीं था. वह हित साधने वाले लोग कोई और थे जिसके लिए कांग्रेस लड़ रही थी. अस्पृश्यता का हल जिससे नहीं निकलता हो, उस धड़े से कोई बड़ा से बड़ा लाभ भी डॉ. आंबेडकर को दे दिया जाए, वह उन्हें स्वीकार नहीं था. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 17, पृष्ठ 3 का अवलोकन करें, डॉ. आंबेडकर ने साफ़ साफ कहा था कि

भारत में आजादी का जो कोलाहल मचा है, उसमें यदि कोई वस्तु है तो वह है अछूतों का हेतु. हिंदुओं और मुसलमानों की लालसा स्वाधीनता की आकांक्षा नहीं है। यह तो सत्ता संघर्ष है, जिसे स्वतंत्राता बताया जा रहा है. इसी कारण मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि किसी दल अथवा किसी संगठन ने अपने आप को अछूतों के प्रति समर्पित नहीं किया. वह वस्तुतः पूरी तरह से उलझे भारत और औपनिवेशिक सभ्यता को भली प्रकार समझ रहे थे और यह आक्रोश भी व्यक्त कर रहे थे कि कितनी चालाकियों के साथ दल, लोग और औपनिवेशिक सत्ता खेल खेल रही है.

जब देश में यह सब चल रहा था तो डॉ. आंबेडकर की चिंता यह थी कि भारत की भोली-भाली जनता कितना छली जा रही है. वांग्मय के 17वें खंड का पृष्ठ 82 पर एक उद्धरण देख हैरानी होती है कि उन्होंने कांग्रेस की चालबाजियों को जन-जन तक पहुँचाया और और कहा कि अनभिज्ञ और लापरवाह व्यक्ति भले ही कांग्रेस की भावना को न जानता हो, परंतु वास्तविकता यह है कि वे वामपंथी और प्रगतशील नेता आंख मूंदकर उस कांग्रेस का समर्थन करते हैं, जो पूंजीपतियों, जमींदारों, सूदखोरों तथा प्रतिक्रियावादियों द्वारा चलाई जा रही है- केवल इसलिए कि कांग्रेस अपने कार्यकलापों द्वारा स्वतंत्रता का गौरवान्वित नाम लेकर चिल्ला-चिल्ला कर प्रचार करती हैं. उनका दूसरा सबसे बड़ा आरोप था वह था सवर्णों पर. वह यह जानते थे की सवर्ण ही कांग्रेस है. इसलिए उन्हें आशंका थी कि वे ही सत्ताधीश होकर भारत के दलित व दमित को स्वाधीनता के वास्तविक जीवन को पाने ही नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि इतिहास के अनुसार वे भारत की शासक जातियों में सब से अधिक शक्तिशाली और अधिकार संपन्न हैं. यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि वे शासित वर्ग के घोर शत्रु हैं. उन्होंने शासितों के छः सूत्रों को रेखांकित किया है-एक, विभिन्न वर्गों में असमानता, दूसरा, शुद्रों और अछूतों की पूरी बेबसी, तीसरा, शूद्रों और अछूतों के लिए शिक्षा द्वार बंद होना, चौथा, सत्ता और अधिकार से शुद्रों और अछूतों को पूर्णतः वंचित रखना, पांचवां शूद्रों और अछूतों को संपत्ति संचय से वंचित रखना और छठा, स्त्रियों की पूर्ण अधीनता एवं दमन. शासित तबके जिसकी वजह से शूद्रों की स्थिति ख़राब थी उन दिनों निःसंदेह प्रश्न खड़े कर रही थी.

31 दिसंबर 1939 को सतारा के भाषण में उन्होंने कहा कोई मुझे कोसे तब भी मुझे डर नहीं लगता. सार्वजनिक कामों में पैसों की जरूरत पड़ती है यह आप भी जानते हैं. गांधी जी ने एक करोड़ रुपयों का फंड इकट्ठा किया और वह सब खर्च हो गया इस बारे में आपने सुन रखा होगा. जनाब जिन्ना को भी सार्वजनिक कामों के लिए रुपयों की मदद मिलती ही होगी. मेरे समाज के आज तक मुझे रु. 5000 से अधिक मदद प्राप्त नहीं हो पाई है. यह बात गौर करने लायक है। अपनी गरीबी के कारण हमें धन की कमी के साथ ही काम करना पड़ेगा यह जाहिर बात है. हमें आपस में एकता रखना होगा। फूट नहीं पड़ने देनी है। आज राजनीतिक हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि गांधी, जिन्ना तथा अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के रूप में मैं-हमें कुछ पूछे बगैर हिन्दुस्तान का राजनीतिक मसला हल नहीं होता. अंग्रेज व्यक्ति डॉ. थॉमसन ने यह बात मुझे और गांधी जी को बताई है. कॉंग्रेस चाहे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, राक्षस, राष्ट्रद्रोही, आस्तीन का सांप वगैरा कुछ भी कहे, वे मुझे खारिज नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं गांधी जी जैसा महात्मा नहीं हूँ। मेरे साथ आप लोगों की अभेद्य एकता का कवच है.

डॉ. आंबेडकर का क्या वह तेवर और विश्वास, लक्ष्य व योजना, नैतिक साहस और त्याग किसी में बचा है? यदि नहीं बचा है तो हम उनके विभिन्न अवसरों पर केवल उन्हें याद करके रस्म अदायगी कर रहे हैं तो यह उनके प्रति कृतज्ञता नहीं है. डॉ. आंबेडकर आज इस अवसर पर हमसे एक कृतज्ञ व समर्पित-जन की अपेक्षा करते हैं.

पुण्यतिथि विशेष

रघु ठाकुर
लेखक समाजवादी चिंतक हैं।

जाति का विनाश और जन्मना बराबरी ही होगी बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि

6 दिसम्बर बाबा साहब की पुण्यतिथि है तथा कई प्रकार से यादगार का दिन है। इतिहास के उन पन्नों को खोलने का भी दिन है जो डॉ. लोहिया और बाबा साहब के बीच में चल रहे वार्तालाप के अंतिम निष्कर्ष के पहुंचने के पहले ही समाप्त करने वाला दुःखद दिन बन गया। बाबासाहब अम्बेडकर और लोहिया के बीच मिलकर काम करने का निर्णय मानसिक तौर पर लगभग तय हो चुका था और बाबा साहब ने पत्र लिखकर दिसम्बर माह में ही लोहिया को बातचीत के लिये दिल्ली आंमत्रित किया था। परन्तु बातचीत की तिथि के कुछ दिनों पूर्व ही बाबा साहब का दुःखद निधन हो गया और एक बड़ी सामाजिक और वैचारिक क्रांति की उभरती संम्भावनायें समाप्त हो गई। चूंकि 6 दिसम्बर को ही आयोध्या में राममंदिर के निर्माण के आंदोलनकारियों या उपद्रवियों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था तथा 6 दिसम्बर 92 की इस घटना के बाद सारा देष साम्प्रदायिक तनाव में विभाजित हो गया था। बाबा साहब की पुण्यतिथि का दिन जो संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का दिन होना चाहिये वह साम्प्रदायिक तनाव में विभाजित हो गया था। और हालत यह है कि जिस 6 दिसम्बर को भारत के संविधान पर चर्चा होना चाहिये संविधान को कितना लागू कर पाये या और क्या होना चाहिये, इसके बजाय 6 दिसम्बर को एक ऐसे दिन में बदल दिया गया जिससे ये मूल प्रश्न पीछे चले गये। भारतीय समाज और राजनीति की त्रासदी व विसंगति है कि वह विमर्ष के उन मुद्दों से छिटक गई है जो राष्ट्र के लिये जरुरी है। बाबा साहब चाहते थे कि देश में समाजवादी व्यवस्था कायम हो और वे तो संविधान के मूल अधिकार में उसे शामिल करना चाहते थे, ताकि सामाजिक कार्यक्रम या समता के कार्यक्रम किसी राजसत्ता के मुहताज न हो तथा संविधानिक अधिकार के रुप में नागरिक उन्हें हासिल कर सकें। भले ही 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया हो, परन्तु समता के कदमों को अमल में नहीं लाया गया। अगर संवैधानिक समाजवाद स्थापित हुआ होता तो आज देश में जो विषमता बढ़ रही है अमीरी के टापू खड़े हो रहे है और गरीबी की खाई गहरी हो रही है, वह नहीं हुई होती। भारत के अनुसूचित जाति के लोगों ने भी बाबा साहब को पूज्यनीय बुत में सीमित कर दिया है। उनकी स्मृति में बड़ी संख्या में देश में अनुसूचित जातियों के लोग एकत्रित होते हैं उनकी आराधना करते है परन्तु उनकी कल्पना के भारत के निर्माण पर चर्चा नहीं ही करते। मैं 14 अप्रैल उनके जन्मदिवस और 6 दिसम्बर की पुण्यतिथि आयोजनों में अमूमन कहीं न कहीं हिस्सेदार होता हूं और इस आयोजनों की औपचारिकता तथा शाब्दिक व्याख्यानों को सुनता हूं। मैं उनमें खोजने का प्रयास करता हूं कि क्या बाबा साहब के विचारों पर कुछ चिंतन, मनन उनकी स्थापना के लिये पीड़ा या वेदना और संकल्प है पर शायद कही भी नजर नहीं आता। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि सत्ता प्रतिष्ठान एक संस्थागत लाचारी की औपचारिकता पूरी करता है और अनुसूचित जाति समाज के लोग भी बाबा साहब को जाति दायरे से बाहर निकालने का कोई प्रयास नहीं करते। कितने अनुसूचित जाति के नेताओं ने बाबा साहब और लोहिया के पत्राचार को पढ़ने का कष्ट किया है? उनका संवाद किन किन बिन्दुओं पर था? वे नजदीक आकर कैसा समाज बनाने के लिये संघर्ष करते? उनके सपने के समाज को साकार करने के लिये अब हमारे दायित्व क्या है? राजनीति की क्या दिशा इस उद्देश्य के लिये होना चाहिये। ऐसे गम्भीर प्रश्नों पर कोई चिंतन मनन नजर नहीं आता। बाबासाहब एक परिवर्तनशील विचार के व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतः लिखा कि हमें विचारों के मामले में आने वाली पीढ़ी के लिये बांधना नहीं चाहिये। वे पुरातन पंथी या लकीर पीटू नही थे। बल्कि समाज की वास्तविकताओं और पीड़ाओं का एहसास कर उसके लिये मार्ग खोजने का प्रयास करते थे। आज अगर बाबासाहब होते तो वे किस प्रकार के बदलाव का प्रयास करते इसके संकेत उनके लेखन और विचार से मिल जाता है। वैश्वीकरण और निजीकरण उनके विचारों के विपरीत है। वे तो प्रमुख उद्योगों और विषयों को सरकार के माध्यम से समाज के नियंत्रण में रखने के पक्षधर थे। वे निजीकरण के खिलाफ थे। परन्तु वैश्वीकरण जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का निजीकरण करने वाली प्रक्रिया है, को बाबा साहब कभी स्वीकार नहीं करते। देश में साम्प्रदायिक, मानसिक विभाजन की रेखा को मजबूत करने के लिये शायद दुनिया की कारपोरेटलॉबी ने जानबूझ कर 6 दिसम्बर का दिन चुना था ताकि बाबा साहब की वैचारिक स्मृतियों को पीछे धूमिल किया जा सके तथा मानसिक विभाजन इतना गहरा हो जाये कि बाबा साहब के स्थापित लक्ष्य समानता, संवैधानिक समाजवाद, राष्ट्रीय करण आदि पर चर्चा न हो सकें।

बाबा साहब के मानने वालों के या उनके प्रति सम्मान प्रकट करने वालों में तीन प्रकार के लोग हैं।

1. सत्ता प्रतिष्ठान की औपचारिकता निभाने वाले समूह जिनके लिये वह लगभग वैधानिक प्रशासनिक और औपचारिक लाचारी है।

2. उनके जन्मना जाति समूह के लोग जो उन्हें पूज्यनीय, वंदनीय और भगवान जैसा स्थापित कर बुत परस्ती करते हैं पर जिन्हें उनके विचारों से कोई लेना देना नहीं है।

3. हमारे जैसे लोहियावादी, समाजवादी जो बाबा साहब के विचारों में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता के विचारों तथा बदलाव के सूत्र खोजते हैं तथा उन्हें कैसे जमीन पर उतारा जाये इसके लिये चिंता व प्रयास करते है। गौतम बुद्ध ने तर्क आधारित और विवेक संगत समाज की स्थापना की पहल की थी। वे कहते थे कि किसी बात को तब तक न मानो जब तक उससे सहमत न हो जाओ। उनके दर्शन ने भारतीय समाज की जातिगत जड़ता को हिलाया डुलाया था और धर्म के नाम पर चल रहे पाखण्ड, षोषण और पुरोहितवाद को कमजोर किया था। सामाजिक रुप से कमजोर माने जाने वाले लोगों में एक चेतना-बराबरी की ललक-तर्क एवं योग्यता तथा अन्धविश्वास को नकारने का साहस बुद्ध ने दिया था। महात्मा गांधी ने भी भारतीय समाज को जो हजारों साल के राजतंत्र और सामंतवाद के प्रभाव से भीरु और सपना विहीन समाज बन गया था को निर्भय बनाकर उनके सामने एक मानवीय सभ्यता का सपना प्रस्तुत किया था। बाबा साहब ने शायद इसलिये धर्म-परिवर्तन के नाम पर बुद्ध को चुना था क्योंकि बुद्ध उनके लिये धर्म दर्शन और आध्यातमिक तौर पर सबसे नजदीक दिखते होगे। कुछ लोग अभी भी बाबा साहब के नाम से गांधी की आलोचना करने के खेल में फंसे रहते हैं। यह उनकी अज्ञानता भी हो सकती है और अतीत जीवी दकियानुसीपन भी। ऐसे लोग ''पूनापेक्ट'' को लेकर गांधी की आलोचना करना अपनी शान और बुद्धिता समझते हैं। वे भूल जाते हैं या अपने राजनैतिक हितों के लिये जानबूझकर उन घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहते जो इतिहास में दर्ज है। पूनापेक्ट के बाद जब कुछ तत्कालीन अनुसूचित जाति के बुद्धिजीवियों ने पूनापेक्ट की आलोचना शुरु की तो उसका उत्तर स्वतः बाबा साहब ने अपनी सभाओं के माध्यम से दिया था। उन्होंने कहा कि ''जो लोग यह मानते है कि पूनापेक्ट से कुछ भी हासिल नहीं हुआ वे गलती पर है। पूनापेक्ट से बहुत कुछ हासिल हुआ है।'' आज अगर भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को विधायिका और शासकीय सेवाओं में आरक्षण मिला है तथा जनतांत्रिक भूमिकाओं में उनका स्थान सुरक्षित है तो वह उस समझौते का ही परिणाम है। इन जाति नेताओं को इस बात का ऐहसास नहीं है कि गांधी को पूनापेक्ट के बाद कट्टरपंथी समाज ने कितनी गालियां दी थी और उनके प्रति कितनी घृणा का प्रदर्शन किया था। वह तो गांधी थे जो शिव के समान हलाहल खुद पी रहे थे और अमृत की जितनी बूंदे निकली वे अनुसूचित जाति के भाईयों को ही दे रहे थे। बाबा साहब ट्रेड यूनिस्ट थे और तोप की मांग कर रिवाल्वर लेने की रणनीति के प्रखरज्ञाता थे। मजदूर आंदोलन में सौदेबाजी एक (कलेक्टिव बारगे निंग) स्वीकृत तरीका रहा है और बाबा साहब इस का चतुर प्रयोग गांधी के साथ करते थे। गांधी भी उनके विरोध और आक्रमण को हंसकर स्वीकारते थे तथा समाज के पीछे वाले लोगों दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों को समता के कुछ कदम आगे बढ़ाने के माध्यम बन जाते थे।

मुझे बाबा साहब व गांधी के बीच विशेषतः 1940 के बाद कोई वैचारिक गहरा अन्तर नहीं दिखता। बल्कि कई बार तो वे एक-दूसरे के पूरक नजर आते हैं। आग्रह और स्वीकारता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। गांधी, बाबा साहब के आग्रहों को हिन्दू समाज की जड़ता को खत्म करने समता का व्यवहार करने और बदलने के लिये प्रेरित करने का माध्यम मानते थे। गांधी बाबा साहब के आक्षेप या आरोपों को नकारने के बजाय स्वीकार करते थे। जब गांधी से पूछा गया कि ''अम्बेडकर उनकी अलोचना करते हैं'' तो गांधी ने कहा कि'' हमारे पुरखों ने जो अत्याचार दलितों के साथ किया है उसका प्रायश्चित हमें करना होगा और उनकी गलतियों को भी स्वीकार करना होगा।'' यह गांधी ही थे कि जिन्होंने संविधान सभा में बाबा साहब को लाने का निर्देश जो एक प्रकार से आदेश जैसा ही था नेहरु को दिया था। यह गांधी ही थे कि संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष पद के लिए स्वः जवाहरलाल जी को अम्बेडकर का नाम प्रस्तावित किया और स्वीकार करने के लिये सहमत कराया था। बाबा साहब के मन के भीतर गांधी के प्रति जो भाव था वह एक घटना से सिद्व होता है कि गांधी की मौत के बाद बाबा साहब ने जब दूसरी शादी श्रीमति सविता अम्बेडकर से की तो स्वः बल्लभभाई पटेल से पत्र में और स्वः प्यारे लाल जी से बातचीत में कहा कि आज अगर बापू होते तो कितने खुश होते और मुझे आर्शीवाद देते। क्योंकि गांधी ने अपने जीवन के आखिरी वर्षो में यह निर्णय कर लिया था कि वे किसी समान जाति के लोगों के विवाह में नहीं जायेंगे न उन्हें आर्शीवाद देंगे। वे केवल ऐसे विवाहों में ही आर्शीवाद देंगे जहां विवाह अंतर्जातीय हो जो ऊपर व नीचे की जातियों के बीच हो। आजकल कुछ सुशिक्षित वैश्वीकरण के समर्थक अनुसूचित जाति के नेता व बुद्धिजीवी दलित पूंजीवाद की चर्चा करते हैं। वे दलितों में से कुछ लोगों को पूंजीपति बनाना चाहते हैं और इसे दलितों या अनुसूचित जाति का विकास मानते और बताते हैं। अगर दलितों में या अनुसूचित जाति के लोगों में कुछ लोग पूंजीपति बन जाये तो क्या इससे समता स्थापित होगी? बाबासाहब तो पूंजीवाद और ब्राम्हणवाद (यानि जन्मना के विचार श्रेष्ठता) के खिलाफ थे और उन्हें मिटाना चाहते थे। रेल कर्मचारियों की एक सभा को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा था कि मेरे दो शत्रु हैं 1. पूंजीवाद, 2. ब्राम्हणवाद । परन्तु कुछ उनके नाम का उल्लेख करने वाले सामाजिक नेता आज इन दोनों ही बुराईयों को अंगीकार कर रहे है।

बाबासाहब की स्मृतियों को नमन करते हुये अब संकल्प लेना होगा कि हम पूंजीवाद को मिटाकर समाजवाद लाने का प्रयास करेगे, जातिवाद को मिटाकर बराबरी का समाज बनाने की पहल करेंगे और अंधविश्वासी, कट्टरपंथी समाज को बदलकर तार्किक और वैज्ञानिक समाज बनाने की पहल करेंगे यही बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

पुण्यतिथि विशेष

डॉ.सौरभ मालवीय
लेखक मीडिया शिक्षक हैं।

आंबेडकर, समरसता और संघ

देश में सामाजिक समता एवं सामाजिक न्याय के लिए प्रमुखता से स्वर मुखर करने वालों में डॉ. भीमराव आम्बेडकर का नाम अग्रणीय है। उन्होंने बाल्यकाल से ही अस्पृश्यता का सामना किया था। विद्यालय से लेकर नौकरी तक उन्होंने भेदभाव का दंश झेला। इससे उनकी आत्मा चीत्कार उठी। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने देशभर की यात्रा की तथा दलितों के अधिकारों के लिए स्वर मुखर किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अस्पृश्यता के उन्मूलन के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि सेवक बनकर ही कोई बड़ा कार्य किया जा सकता है। इसलिए वह कहते थे- 'एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है।'

डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने सामाजिक समरसता का जो स्वप्न देखा था, उसे साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभियान चला रहा है। वास्तव में संघ अपने स्थापना काल से ही सामाजिक समरसता के लिए कार्य कर रहा है। डॉ. केशव बलिराम हेडगवार ने सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता एवं सशक्त समाज के निर्माण के उद्देश से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। उनका कहना था कि हमारा निश्चय एवं स्पष्ट ध्येय ही हमारी प्रगति का मूल कारण है। हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि जिस कार्य को करने का हमने प्रण किया है, और जो उद्देश्य हमारे सामने है, उसे प्राप्त करने के लिए हम कितना कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक अधिकारी एवं शिक्षक को प्रत्येक के मन में यह विचार भर देना चाहिए कि मैं स्वयं ही संघ हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र पर विचार करना चाहिए। अपने चरित्र को कभी भी कमजोर व क्षीण न होने दें। आप इस भ्रम में न रहें कि लोग हमारी ओर नहीं देखते। वे हमारे कार्य तथा हमारे व्यक्तिगत आचरण की ओर आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। हमें केवल अपने कार्य में व्यक्तिगत चाल-चलन की दृष्टि से सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, अपितु सामूहिक एवं सार्वजनिक जीवन में भी इसका ध्यान रखना चाहिए।

वह कहते थे कि बिना कष्ट उठाए और बिना स्वार्थ त्याग किए, हमें कुछ भी फल मिलना असंभव है। अपने समाज में संगठन निर्माण कर उसे बलवान तथा अजेय बनाने के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं करना है। इतना कर देने पर सारा कार्य स्वयं ही हो जाएगा। हमें आज सताने वाली सारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। अनुशासन अपने संगठन की नींव है, इसी पर हमें विशाल इमारत को खड़ा करना है। किसी भी भूल से यदि नींव जरा सी भी कच्ची रह गई, तो इमारत का उस ओर का भाग ढल जाएगा। इमारत में दरार पड़ जाएगी और आखिर में वह संपूर्ण इमारत ढह जाएगी। जीवन में निस्वार्थ भावना आए बिना खरा अनुशासन निर्माण नहीं होता।

सामाजिक समरसता के बारे में उनका कहना था कि संघ का लक्ष्य भारत राष्ट्र को पुनः परम वैभव तक ले जाना है। समरसता के बिना, समता स्थायी नहीं हो सकती, और दोनों के अभाव में राष्ट्रीयता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा कार्य अखिल हिंदू समाज के लिए होने के कारण, उसके किसी भी अंग की उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा। सभी हिंदू भाइयों के साथ फिर वह किसी भी उच्च या नीच श्रेणी के समझे जाते हों, हमारा व्यवहार हर एक से प्रेम का होना चाहिए। किसी भी हिंदू भाई को नीच समझकर उसे दुत्कारना पाप है। वह कहते थे कि संघ का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें लोक संग्रह के तत्वों को भली भांति समझ लेना होगा। संघ केवल स्वयंसेवकों के लिए नहीं, अपितु संघ के बाहर जो लोग हैं, उनके लिए भी है। हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि उन लोगों को हम राष्ट्र के उद्धार का सच्चा मार्ग बताएं। वयोवृद्ध लोगों का संघ कार्य में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। वे संघ के महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व उठा सकते हैं। यदि प्रौढ़ लोग अपने प्रतिष्ठा और व्यवहार कुशलता का उपयोग संघ कार्य किए तो करें, तो युवा अधिक उत्साह से कार्य कर सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को उत्साह और हिम्मत से आगे आना चाहिए, और संघ कार्यों में जुट जाना चाहिए। इस समाज को जागृत एवं संगठित करना ही राष्ट्र का जागरण एवं संगठन है। यही राष्ट्र धर्म है। ध्येय पर अविचल दृष्टि रखकर, मार्ग में मखमली बिछौने हो या कांटे बिखरे हों, उनकी चिंता न करते हुए निरंतर आगे ही बढ़ने को दृढ़ निश्चय वाले क्रियाशील तरुण खड़े करने पड़ेंगे। पूर्ण संस्कार दिए बिना, देशभक्ति का स्थाई स्वरूप निर्माण होना संभव नहीं है तथा इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होने तक सामाजिक व्यवहार में प्रमाणिकता भी संभव नहीं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने सामाजिक समरसता पर विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि समरसता के लिए आत्मग्लानि दूर करने के लिए आत्मबोध को जगाना पड़ेगा, स्वार्थ के स्थान पर निस्वार्थ भाव का निर्माण करना पड़ेगा। सभी भेदों को भुलाकर एकात्मकता का भाव जागृत करना पड़ेगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। महात्मा गांधी भी संघ के कार्यों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने वर्ष 1934 में वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शिविर देखा था, जिसमें सभी जातियों के लोग सम्मिलित हुए थे। इसमें दलित समाज के लोग भी थे। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि आपके संगठन में अस्पृश्यता का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूं।

इसी प्रकार डॉ. भीमराव आम्बेडकर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों से प्रभावित हुए थे। उन्हें वर्ष 1939 में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविर को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि शिविर में सभी जातियों के लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसमें दलित समाज के लोग भी सम्मिलित थे। शिविर में सबके साथ समान व्यवहार किया जा रहा था।

उल्लेखनीय है कि हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में समरसता का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। भगवदगीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है- 'पंडिताः समादर्शिनः' अर्थात् विद्वान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कहने का अभिप्राय है कि विद्वान सबको समान मानते हैं तथा वे किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते।

भीमराव आम्बेडकर समानता पर सर्वाधिक बल देते थे। वह कहते थे कि अगर देश की अलग-अलग जातियां एक दूसरे से अपनी लड़ाई समाप्त नहीं करेंगी, तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते , हमारे पास यह आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सकें, जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरोधी हैं। एक सफल क्रांति के लिए केवल असंतोष का होना ही काफी नहीं है अपितु इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है, वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी हैं। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्म-शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए।

भीमराव आम्बेडकर ने दलित समाज के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका कहना था कि आप स्वयं को अस्पृस्य न मानें, अपना घर साफ रखें। पुराने और घिनौने रीति-रिवाजों को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास यह आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेद-भाव और अन्य चीजों से भरी हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी हैं। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है, जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए।

वह कहते थे कि आदि से अंत तक हम सिर्फ एक भारतीय है। हम जो स्वतंत्रता मिली हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली हैं। जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। स्वोतंत्रता का अर्थ साहस है, और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। वह यह भी कहते थे कि देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। पानी की बूद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का वन स्वतंत्र है। वह सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ, अपितु स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि हम लोगों को समझना चाहिए कि लौकिक दृष्टि से समाज को समर्थ, सुप्रतिष्ठित, सद्धर्माघिष्ठित बनाने में तभी सफल हो सकेंगे, जब उस प्राचीन परंपरा को हम लोग युगानुकूल बना, फिर से पुनरुज्जीवित कर पाएंगे। युगानुकूल कहने का यह कारण है कि प्रत्येक युग में वह परंपरा उचित रूप धारण करके खड़ी हुई है। कभी केवल गिरि-कंदराओं में, अरण्यों में रहने वाले तपस्वी हुए तो कभी योगी निकले, कभी यज्ञ-यागादि द्वारा और कभी भगवद्-भजन करने वाले भक्तों और संतों द्वारा यह परंपरा अपने यहां चली है।

बगैर सीमांकन किए ही निर्माण कार्य शुरू हुआ..

विधायक निर्माण कार्य योजना का होर्डिंग विस्तार से लगवाने की पहल करें ना..?

नर्मदापुरम। करोड़ों की भूमि पर आखिरकार षड्यंत्र कारियों की योजना मूर्तरूप लेने लगी। ऐतिहासिक बजरिया स्कूल को षड्यंत्र पूर्वक जमींदोज कर योजना बद्ध तरीके से शनैःशनैः उसे अपने कब्जे में करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया। पहले चरण में बजरिया स्कूल के सामने विस्थापित फल वालों की आड़ बनाकर आने-जाने वालों की नजर में पड़ने वाली स्कूली गतिविधियां अवरोधित की और अब उन्हीं फल वालों को नीचे सड़क पर उतारकर बगैर सीमांकन किए इस क्षेत्र को टीन की चादरों से ढांक कर अंदर क्या काला पीला कर रहे देखने से

वंचित किया जा रहा..? लगभग 55 हजार पांच सो फुट का बेशकीमती रकबा यहां राजनीतिक रसूख की आड़ बनाकर अघोषित कब्जे में किया जा चुका है। अतिक्रमण में पहले यहां एनईएस शिक्षा संस्थान का कब्जा था। एनईएस शिक्षा संस्थान को रातों रात हटाकर इस जगह अब शिक्षाविद् रहे पं रामलाल शर्मा के नाम का इस्तेमाल कर उनके वारसानों ने स्कूल स्थापित कर उनके वारसानों ने आधिपत्य जमा लिया और अब नगरपालिका स्वामित्व वाली जगह टीन से घेर आडिटोरियम निर्माण रुपरेखा संचालित करवा दी गई। लुक-छिपकर होने वाले निर्माण पर लोग सवाल कर रहे बजरिया स्कूल की जगह निर्मित हो आडिटोरियम का ब्लूप्रिंट सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। विधायक को चाहिए ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य का चित्र सहित कार्ययोजना का होर्डिंग्स विस्तार पूर्वक लगवाने की पहल करें मसलन कितने क्षेत्रफल में आडिटोरियम निर्माण होगा, कितने पहुंच मार्ग होंगे, उसके रखरखाव के लिए केंपस में कितनी दुकानें खुलवाई जायेगी, उसकी बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी या नहीं बगैरा बगैरा जिससे लोगों को मालूम तो हो प्रशासनिक योजना का सोशल मीडिया में विरोध जतलाने वाले उनके जनप्रतिनिधि आखिर कितने पानी में हैं।

हफ्ता वसूली करने वाला अपराधी गिरफ्तार

लोगों को डरा धमका शराब पीने के रूपये की करते थे वसूली, औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

देवास। देवास पुलिस की सक्रियता से इन,दिनों गुंडे बदमाशों में खौफ का वातावरण है। दिनांक 03.12.2024 को फरियादी पवन पिता विनोद मेहरा जाति माझी उम्र 22 साल निवासी बालगढ मल्टी देवास रिपोर्ट किया कि घर के बाहर मल्टी से निकला तो मल्टी मे रहने वाले रोहित, बिजू उर्फ बक्शा, राहुल , सावन आये और बोला की यह मल्टी मे रहना है तो हमे दारु पीने के लिये 1000 रुपये हफ्ता देना पड़ेगा ।

रुपये देने से मना किया तो चारो बोले की तु हमे अभी पहचाना नही है हमारे थाने पर कई रिकार्ड है और माँ बहन की नंगी नंगी गालिया देने लगे। और रोहित व राहुल दोनो ने अपनी पेंट मे से बेल्ट निकालकर मारपीट की जिससे चोट लगी और बिजू और सावन ने थाप्पड मुक्की से मारपीट की ।

फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रं. 1277/2024 धारा- 296,115(2),351(3) ,119(1),3(5) बी एन एस का पंजीबद्ध किया गया जिसपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय देवास श्री पुनीत गेहलोद द्वारा हफ्ता वसुली करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु विशेष प्रयास करने एवं आपरेशन हवालात चलाने आदेश दिये गये थे जिस पर से श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जयवीरसिंह भदौरिया एवं देवास नगर पुलिस अधीक्षक श्री दीशेष अग्रवाल द्वारा हफ्ता वसूली के बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी थाना औद्योगिक क्षेत्र निरीक्षक शशिकांत चौरसिया को निर्देशित किया गया था ।

पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उक्त आदेश के पालन में प्रकरण के आरोपियों की तलाश कर दिनांक 04.12.2024 को आरोपी सावन डोडिया पिता सूरज डोडिया उम्र 29 साल निवासी बालगढ मल्टी देवास को गिरफ्तार किया गया जिसे हवालात में रखा जाकर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर जेल भेजा गया है अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर लगातार अपराधियों पर समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

सराहनीय कार्य - उक्त सराहनीय कार्य में निरीक्षक शशिकान्त चौरसिया थाना प्रभारी थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास, प्र.आर. गोपाल, आर. नरेन्द्र, संदीप थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास की सराहनीय भूमिका रही।

घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी धराए

थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने किया गिरफ्तार, घर में जबरन घुसकर मारपीट कर दी धमकी,पुलिस ने तत्काल कार्यवाही कर पकड़ा

देवास। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 03.12.2024 को फरियादी संगीता गुर्जर पति मुन्नालाल गूर्जर उम्र 44 साल निवासी बालगढ़ मल्टी देवास ने रिपोर्ट किया कि रात को करीब 7.30 बजे फरियादिया उसकी बहु के साथ घर पर थी तभी सोनु दरबार ,चाँदनी दरबार व उसका भतिजा और अन्य साथी ने उनके साथ माँ बहन कि नंगी नंगी गालियाँ देते हुये घर में घुस गये और विजु का यही घर् है, फिर इन्होने धक्का मुक्की किया फरियादी का लडका विजु घर् पर नही मिला तो इन लोगों ने जाते जाते किसी दिन भी विजु को जान से खत्म करने की धमकी दी फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रं. 1268/2024 धारा 296,115(2).351 (3), 331(6),3(5) बी.एन.एस की रिपोर्ट दर्ज किया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद द्वारा शहर में गुण्डागर्दी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे जिस पर से श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जयवीरसिंह भदौरिया एवं देवास नगर पुलिस अधीक्षक श्री दीशेष अग्रवाल द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी थाना औद्योगिक क्षेत्र निरीक्षक शशिकांत चौरसिया को निर्देशित किया गया था।

वाहनों की संख्या बढ़ी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के रिक्त पदों पर नहीं हुई पूर्ति

यातायात विभाग में बल की कमी, 22 कर्मचारियों के भरोसे पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था

संजय व्दिवेदी, बैतूल। शहर की आबादी के साथ-साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन सुविधाओं में इजाफा नहीं हुआ है। यहां तक की यातायात विभाग में पुलिस कर्मियों की संख्या भी स्वीकृत बल से मात्र एक तिहाई ही है। ऐसे में जो मौजूदा यातायात पुलिसकर्मी है, उन्हीं के कंधों पर पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी टिकी हुई है। यहीं वजह है कि यदि कहीं जाम लग जाये तो पर्याप्त यातायात बल नहीं होने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था संभलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यातायात कर्मियों को प्रतिदिन चौक चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी करनी पड़ती है। चालानी कार्रवाई के लिए भी प्रधान आरक्षक सहित चार-पांच आरक्षकों की जरूरत पड़ती है। पुलिस चालानी कार्रवाई में व्यस्त रहती है तो इधर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। ऐसे में यातायात विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था बनाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

61 पद स्वीकृत, मात्र 22 कर्मचारी मौजूद - यातायात विभाग बैतूल में निरीक्षक, सूबेदार, उपनिरीक्षक सहित कुल 61 पद स्वीकृत है, जिसमें से वर्तमान समय यातायात विभाग में मात्र 22 अधिकारी सहित पुलिस

कर्मी मौजूद है। इसमें से भी लगभग 4 ऑफिस कार्य के लिए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यातायात विभाग बैतूल में निरीक्षक 1, सूबेदार 2, उप निरीक्षक 3, सहायक उपनिरीक्षक 8, प्रधान आरक्षक 7 और 40 आरक्षक के पद स्वीकृत है। लेकिन मौजूदा समय मात्र 1 सूबेदार, उपनिरीक्षक 1, सहायक उपनिरीक्षक 4, प्रधान आरक्षक 5, आरक्षक 8 और 2 महिला आरक्षक और 1 चालक है, इस प्रकार कुल मिलाकर यातायात विभाग में अभी 22 अधिकारी-पुलिसकर्मी तैनात है।

बार-बार बिगड़ जाती है ट्रैफिक व्यवस्था- शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बिगडने का एक कारण यह भी है कि लोग ट्रॉफिक नियमों को फालों नहीं करते। वाहन चालक मनमर्जी से वाहन सडक़ और सडक़ किनारे खड़ा कर देते है। जिससे सडक़े संकरी हो जाती है और बार-बार जाम लगता है। इसके अलावा साप्ताहिक बाजार के दिन कोठीबाजार क्षेत्र में वाहन चालक 20-20 मिनट से ज्यादा समय ट्रॉफिक जाम में उलझकर रह जाते है। खासकर लल्ली चौक, कमानी गेट पर यह हालात प्रति रविवार और गुरूवार को निर्मित होते है। गंज, टांगा चौक, कॉलेज चौक, बस स्टैंड, मुल्ला पेट्रोल पंप सहित सदर के साप्ताहिक बाजार का भी यहीं हाल रहता है। बडोरा ओवरब्रिज पर अधिकतर समय जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। यहां ट्रैफिक कर्मियों को यातायात सुचारू करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पडता है। सबसे ज्यादा परेशानी यातायात पुलिसकर्मियों की कमी के कारण होती है।

अब अखरने लगी पार्किंग प्वॉइंट की कमी

शहर के साप्ताहिक बाजार में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां वाहन खड़े किए जा सकें। अभी तक शहर को पार्किंग प्वाइंट की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर अब वाहनों के बढ़ने के कारण पार्किंग नहीं होने से बाजार में समस्या बन रही है। सड़क के दोनों तरफ दुकाने और वाहनों पर बैठकर ही खरीदी करने वाले लोगों की वजह से सड़क़ सिकुड़क़र कम चौड़ी रह जाती है। ऐसे में यदि कोई भारी वाहन इस सडक पर आ जाये तो अन्य वाहन का निकल पाना मुश्किल हो जाता है। परिणाम लंबा-चौड़ा जाम लगने से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती है। बता दे कि कोठीबाजार सडक काफी व्यस्त सडको में शामिल है। इस सड़क पर दिन भर वाहनों आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में वाहनों की अघोषित पार्किंग के कारण काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।

ट्रैफिक व्यवस्था के साथ-साथ अन्य जिम्मेदारियां भी

यातायात पुलिस पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बनाये रखने के अलावा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना, स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देना और ट्रॉफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना सहित अन्य जिम्मेदारियां है। समय-समय पर एडवाइजरी जारी कर नियमों की सूचना आमजन तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वीवीआइपी मूवमेंट के दौरान भी यातायात पुलिस को तैनात किया जाता है। लेकिन इन सब एक्टीविटी के अनुरूप बल मौजूद नहीं है। फिर भी यातायात पुलिस सीमित संसाधनों के जरिए अधिकतम नतीजे प्राप्त करने का प्रयास करती है, ताकि लोगों को परेशानियां न हो।

यातायात पुलिस ने 50 वाहनों के बनाए चालान, 7 हजार वसूला समन शुल्क

बैतूल शहर में यातायात पुलिस ने गुरुवार को यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही की। पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया के निर्देशानुसार पहली बार यातायात पुलिस ने कैमरे का भी उपयोग किया है। यातायात थाना प्रभारी सूबेदार गजेन्द्र केन ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश के मुताबिक कैमरा लगाया गया है, ताकि चालानी कार्रवाई में पूर्णरूपेण पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि चालानी कार्रवाई के दौरान अक्सर यातायात पुलिसकर्मियों पर वसूली जैसे आरोप भी लगाए जाते है। चेकिंग अभियान के दौरान कैमरे में पुलिस से बहस करते वाहन चालकों की हरकते

भी कैद की जा रही है, ताकि इनके खिलाफ चालान के साथ-साथ अतिरिक्त कार्रवाई भी की जा सकें। यातायात थाना प्रभारी गजेन्द्र केन ने बताया कि चेकिंग के दौरान तीन सवारी, वाहन चलाते-चलाते मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों पर कार्रवाही की गई। इस दौरान 50 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाही कर 7 हजार रूपये का समन शुल्क वसूल किया है।

इनका कहना

यह सही है कि यातायात पुलिस बैतूल में बल की कमी है। फिर भी हम सीमित संसाधनों के द्वारा अधिकतम नतीजे प्राप्त करने का प्रयास करते है, ताकि आमजनता और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

- गजेन्द्र केन, यातायात प्रभारी, बैतूल

हार्ट अटैक से सीआरपीएफ सब-इंस्पेक्टर का हुआ असामयिक निधन

तिरंगे में लपेटकर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई, गार्ड ऑफ ऑनर से दी गई सलामी

बैतूल। सदर निवासी और सीआरपीएफ में सब-इंस्पेक्टर के रूप नीमच में पदस्थ गणेश प्रसाद साहू को गुरुवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बुधवार शाम करीब 5 बजे सदर स्थित निज निवास में हार्ट अटैक के कारण 55 वर्षीय गणेश प्रसाद साहू का असामयिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गणेश प्रसाद साहू अपने पीछे माता-पिता लक्ष्मी और सुखराम साहू, पत्नी सुनीता साहू, इकलौता बेटा सुमित साहू, बेटी

शीतल साहू, चार भाई रमेश, संतोष, दुर्गेश साहू और एक बहन गीता साहू सहित भरापूरा परिवार छोड़ गए हैं। गुरुवार को उनकी अंतिम यात्रा दोपहर 12:15 बजे सदर स्थित निवास से प्रारंभ हुई, जो गंज मोक्षधाम पहुंचकर संपन्न हुई। अंतिम संस्कार पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया। मुखाग्नि उनके इकलौते बेटे सुमित साहू ने दी। मोक्षधाम में समाज की महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महिलाओं की उपस्थिति ने इस अंतिम यात्रा को खास बना दिया। गणेश प्रसाद साहू को अंतिम विदाई देने के लिए सीआरपीएफ की बटालियन भोपाल से पहुंची। संतोष कुर्वे और राजकुमार दुबे के नेतृत्व में जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर मोक्षधाम तक पहुंचाया। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जवानों ने उन्हें सलामी दी। तिरंगे को उनके बेटे सुमित साहू को सौंपा गया। पूरे क्षेत्र में देशभक्ति के गीत गूंजते रहे। आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने भी उनके निवास पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। विधायक ने सीआरपीएफ की बटालियन से भेंटकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की।

उच्च न्यायालय आदेश के बाद मोक्ष धाम भूमि विवाद निपटारे की कवायद प्रारंभ

ग्राम पंचायत कामथ में हुई विशेष ग्राम सभा

बैतूल/मुलताई। मुलताई नगर की सीमा से लगी ग्राम पंचायत कामथ में शमशान भूमि का विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। तहसीलदार एसडीएम और जिला कलेक्टर आदेश के बाद उच्च न्यायालय पहुंचे उक्त शमशान भूमि विवाद को लेकर आज फिर ग्राम पंचायत कामथ के सामुदायिक भवन में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें सरपंच सचिव के साथ ग्रामीणो के समक्ष पटवारी चंद्रभान भास्कर ने ग्राम पंचायत की भूमि खसरा क्रमांक 165 एवं 168 को मोक्ष धाम के लिए आवंटन का सुझाव दिया जिस पर कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज की । उल्लेखनीय है की पूर्व में ग्राम पंचायत कामथ में मोक्ष धाम के लिए खसरा क्रमांक 145 की 81आरे भूमि जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत को आवंटित की गई थी कुछ ग्रामीण इस भूमि पर मुक्तिधाम बनाए जाने को लेकर यह आपत्ति दर्ज कर रहे थे कि इसके आसपास मकान बने हुए हैं इसलिए भूमि पर मोक्ष धाम का निर्माण नहीं होना चाहिए किंतु मुक्तिधाम निर्माण के पक्षधरों का कहना था कि यह उचित कारण नहीं है और कुछ लोगों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाए हैं।मोक्ष धाम ना होने के कारण लोगों को अपने परिजनों को मुलताई मोक्ष धाम में ले जाना पड़ता है जिसके कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

राजस्व अमले ने पहले नाप के दी भूमि फिर लगाई रोक- ग्रामीण 6 माह से उक्त भूमि को पंचायत के सपुरत करने को लेकर आंदोलन करते रहे ज्ञापन और आवेदनों का सिलसिला तहसीलदार एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक पहुंचा इसके बाद तहसीलदार एव राजस्व अमले ने जिला कलेक्टर द्वारा मुक्तिधाम के लिए आमंत्रित की गई भूमि के खसरा क्रमांक 142 की नपाई करके इसे ग्राम पंचायत के सपुरत कर दिया ताकि वह इस भूमि पर मोक्ष धाम का निर्माण कर सके। किंतु तहसीलदार को भूमि की नपाई करे अभी 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि एसडीएम मुलताई ने इस कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद फिर आवेदन और ज्ञापन का सिलसिला प्रारंभ हुआ जो अभी जारी है और इस बीच मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचा।

उच्च न्यायालय ने दिए मामला निपटने के आदेश- कामथ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की ओर से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत, मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति विवेक जैन के समक्ष याचिका दायर की गई थी जिसमें खसरा क्रमांक 142 क्षेत्रफल 2.889 हेक्टेयर की 0.081 हेक्टेयर भूमि पर मोक्षधाम का निर्माण बिना किसी विलम्ब के तत्काल करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था। याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय ने उप-मंडल अधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका का निपटारा करने के आदेश जारी की है जिसकी प्रक्रिया अब प्रारंभ हो गई है अब यह देखना होगा कि क्या इस विवादित मामले का उचित निपटारा हो पाएगा।

इनका कहना-

कामथ मोक्ष धाम भूमि विवाद को लेकर आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व में आवंटित भूमि के स्थान पर खसरा क्रमांक 165 एवं 168 का सुझाव दिया गया है इस पर कुछ लोगों की आपत्ति है किंतु यह आपत्ति लिखित में नहीं है।

-चंद्रभान बारस्कर,
पटवारी ग्राम पंचायत कामथ

जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन को मिलेगी रिटायरिंग रूम की सौगात

केन्द्रीय राज्यमंत्री-बैतूल विधायक के प्रयासों से राज्यसभा सांसद धर्मेन्द्र प्रधान ने स्वीकृत की थी राशि

बैतूल। जिला अस्पताल बैतूल में भर्ती होने वाले मरीजों के परिजनों (अटेंडरो) को जल्द ही अस्पताल परिसर में ही सर्व सुविधा युक्त रिटायरिंग रूम की सौगात मिलेगी। क्षेत्रीय सांसद, केन्द्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके एवं बैतूल विधायक हेमंत खण्डेलवाल के विशेष प्रयास से राज्य सभा सांसद धर्मेन्द्र प्रधान नें अपनी निधी से रिटायरिंग रूम निर्माण के लिए 84 लाख 98 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की थी। रिटायरिंग रूम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बैतूल विधायक श्री खण्डेलवाल नें निर्माणधीन रिटायरिंग रूम का निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कर गार्डनिंग एंव सौंदर्यीकरण करनें के निर्देश दिये। रिटायरिंग रूम बनने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के परिजनों (अटेंडरो) को रात्रि विश्राम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होनें जिला अस्पताल परिसर में ही सर्वसुविधायुक्त रिटायरिंग रूम में आवासीय और भोजन की सुविधा मिलेगी।

पुरूष-महिला के लिए अलग-अलग होगी आवासीय व्यवस्था - क्षेत्रीय सांसद-केन्द्रीय राज्यमंत्री डी.डी.उइके और बैतूल विधायक हेमंत खण्डेलवाल के विशेष प्रयासों से राज्यसभा सांसद

धमेन्द्र प्रधान की निधी से 84 लाख 98 हजार रुपए की लागत से जिला आस्पताल परिसर में बन रहे रिटायरिंग रूम में भर्ती मरीजों के पुरूष-महिला अटेंडरों के लिए अलग-अलग आवसीय व्यवस्था होगी। रिटायरिंग रूम में पार्टीशन कर पुरुषों-महिलाओं के लिए अलग-अलग रूकने की व्यवस्था की जाएगी। रिटायरिंग रूम में बाकायदा बेड रहेगें साथ ही पंखे,शौचालय सहित अन्य व्यवस्था भी रहेगी।

बेस किचन विथ केंटीन भी रहेगी - जिला अस्पताल में बन रहे रिटायरिंग रूम मे रूकने वाले मरीजों के परिजनों (अटेंडरों) के भोजन नाश्ते के लिए वहा बेस किचन विथ केंटीन भी रहेगी। रिटायरिंग रूम की सुरक्षा एवं साफ सफाई के लिए सिक्योरिटी गार्ड एवं सफाईकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी।

मरीजों के परिजनों को भटकना नही पड़ेगा -उल्लेखनीय है कि आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले के सुदूर ग्रामों एवं पर्वतीय अंचलों से बीमार पीडित ग्रामीण उपचार के लिए जिला अस्पताल आते है। जिला अस्पताल में भर्ती होनें वाले मरीजों के अटेडर परिजनों के सामनें विशेषकर रात्रि में आवासीय व्यवस्था बड़ी चुनौती रहती है। आवासीय व्यवस्था नहीं होनें के कारण सर्दी,बारिश, गर्मी के मौसम में मरीजों के अटेडंर परिजनों को रात्रि विश्राम के लिए भटकना पडता है। अनेक बार अटेंडर परिजनों को अस्पताल परिसर में रतजगा करना पडता है। जिला अस्पताल परिसर में सर्वसुविधायुक्त रिटायरिंग रूम बननें के बाद मरीजों के अटेंडर परिजनों को अस्पताल परिसर में आवासीय व्यवस्था मिल जाएगी। जिससे उन्हें रात्रि विश्राम के लिए न तो भटकना पडेगा और न ही रतजगा करना पडेगा।

विधायक ने दिये सौंदर्यीकरण- गार्डनिंग के निर्देश

राज्यसभा सांसद धमेन्द्र प्रधान की निधी से स्वीकृत जिला अस्पताल में निर्माणाधीन रिटायरिंग रूम का बैतूल विधायक नें निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करनें के निर्देश दिए। रिटायरिंग रूम में रहनें वालें के लिए खुशनुमा माहौल उपलब्ध करानें के लिए बैतूल विधायक हेमंत खण्डेलवाल नें निर्माण एजेंसी को रिटायरिंग रूम के सामने सौंदर्यीकरण-गार्डनिंग करनें के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे,निर्माण एजेंसी,निर्माण कार्य से जुडे इंजीनियर एवं स्वास्थ विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

सृजन

चेतनादित्य आलोक

वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं राजनीतिक विश्लेषक, रांची, झारखंड

परम कल्याणकारी है 'विवाह पंचमी' महोत्सव

सनातन धर्म में प्रायः प्रत्येक महीने का अपना अलग ही धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने का विशेष महत्व इसलिए माना जाता है, क्योंकि यह महीना भगवान श्रीराम, श्रीकृष्ण एवंश्रीहरि विष्णु को समर्पित है। एक ओर जहां इस महीने में सनातन धर्म के अनुयाइयों को भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने हेतु उत्पन्ना एवं मोक्षदा जैसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण एकादशी के व्रत करने का अवसर प्राप्त होता है, वहीं, दूसरी ओर मार्गशीर्ष महीने में पूजा-पाठ, जप-तप, योग-ध्यानादि करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के सभी बिगड़े कार्य बन जाते हैं। विशेष रूप से इस महीने में 'कान्हा मंत्र' का जाप करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बता दें कि भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जब अपनी दिव्य वाणी से गीता का अमर ज्ञान प्रदान किया था, तब उन्होंने स्वयं को 'महीनों में मार्गशीर्ष' बताया था। गीता जी में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- 'बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम। मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकर।' अर्थात् मैं सामों में बृहत्साम, छन्दों में गायत्री, मासों यानी महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसन्त ऋतु हूं। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण ने मार्गशीर्ष महीने का महत्व उद्घाटित किया है।

इसी प्रकार भगवान श्रीराम के भक्तों के लिए भी यह महीना अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है। शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जगत् के नायक भगवान श्रीराम और जगत् जननी माता सीता का शुभ विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत संपन्न हुआ था। इसीलिए इस तिथि को प्रत्येक वर्ष 'विवाह पंचमी' का विशेष कल्याणकारी पर्व देश भर में एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि विवाह पंचमी महोत्सव के शुभ अवसर पर भगवान श्रीराम एवं माता सीता का विवाह कराने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वेसे देखा जाए तो इस महीने में सनातन धर्म के अनुयाइयों के लिए विशेष रूप से शंख की पूजा, नदी या तीर्थ में स्नान और दान करने का भी बड़ा महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष विवाह पंचमी महोत्सव 06 दिसंबर, दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा।

देश भर में आयोजन- गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला यह महोत्सव प्रायः देश के सभी राज्यों में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त इस महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शुभ मुहूर्त में पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ जगन्नायक भगवान श्रीराम एवं जगज्जननी माता सीता के विवाह कार्यक्रम का आयोजन कर भगवान की युगल जोडी की प्रतिमा अथवा तस्वीर की पूजा-अर्चना, आराधना आदि करते अथवा ब्राह्मण से कराते हैं, उन पर भगवान श्रीराम और माता सीता की कृपा बरसती है। इसके परिणाम स्वरूप उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है तथा उनके जीवन में सुख-समृद्धि आती है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही हो, उन्हें विवाह पंचमी के दिन श्रीसीताराम का पूजन एवं 'जानकी मंगल श्रीराम विवाह' उत्सव मनाने से सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यही नहीं, विवाह पंचमी पूजन कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित वर, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और जनमानस को मनोवांछित फल प्रदान करता है।

श्रीरामचरित मानस की रचना इसी दिन पूरी हुई थी- शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवाह पंचमी के दिन ही हिंदुओं के महान ग्रंथ तथा भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथ श्रीरामचरित मानस की रचना भी पूरी की थी। इसलिए इस शुभ अवसर पर 'श्रीरामचरित मानस' का पाठ करने से प्रभु श्रीराम और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है तथा पापों से मुक्ति मिलती है। वैसे, श्रीरामचरित मानस की एक विशेषता यह भी है कि इसके पठन, गायन अथवा श्रवण करने से भक्त के भय एवं शंका का अत्यंत सहजता से निवारण हो जाता है। वैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि समयाभाव के कारण इस संपूर्ण ग्रंथ का पाठ

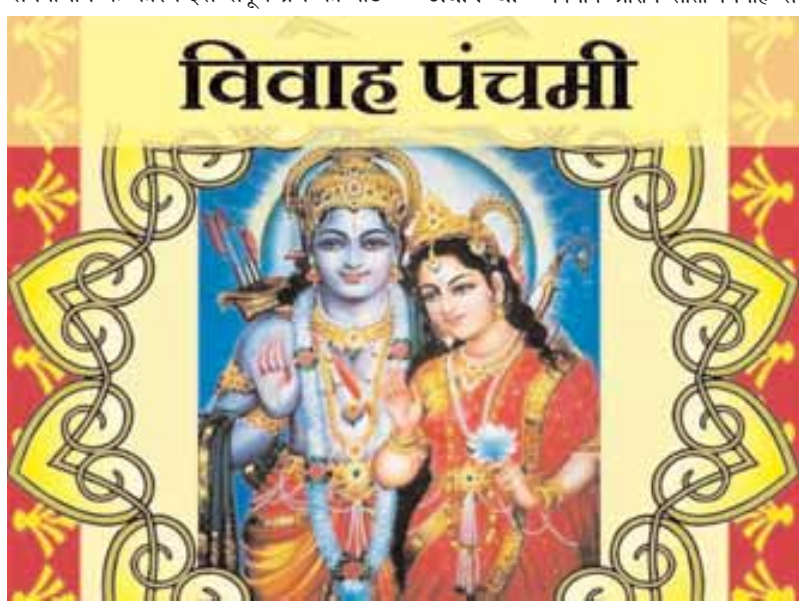

अथवा श्रवण करना संभव न हो, तो कम-से-कम श्रीरामचरित मानस की कुछ प्रमुख चौपाइयों का पाठ अथवा श्रवण अवश्य करना चाहिए।

अयोध्या में दिव्य-भव्य आयोजन- गौरतलब है कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सामान्यतः देश भर के तमाम मठों और मंदिरों, विशेष रूप से भगवान श्रीसीताराम के मंदिरों को सजा-संवार कर भव्य एवं दिव्य रूप प्रदान किया जाता है। इस दिन मंदिरों में चौबीसों घंटे निरंतर भजन-कीर्तन, ध्यान, यज्ञ, पूजा-पाठ और हवन चलता रहता है। वहीं, अयोध्या में प्रत्येक वर्ष विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम एवं भक्ति-भाव के साथ किया जाता है। इस अवसर पर इन मंदिरों से 'श्रीराम रथ यात्रा' भी निकाली जाती है। इस यात्रा में सनातन धर्म के हजारों-लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं।

माता सीता का विवाह धनुष भंग के अधीन था- भगवान श्रीराम-सीता विवाह से संबंधित धर्मग्रंथों में मौजूद एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्रीराम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने के बाद महामुनि विश्वामित्र जी ने महाराज जनक से कहा था कि यद्यपि सीता का विवाह धनुष भंग के अधीन था और धनुष टूटते ही भगवान श्रीराम और माता सीताका विवाह संपन्न हो गया था, फिर भी महाराज दशरथ के पास संदेश भेज कर उन्हें बुलाया जाए और उनकी उपस्थिति में ही श्रीराम-सीता विवाह कर्यक्रम का भव्य एवं दिव्य आयेजन कर उनका विधिवत् विवाह संपन्न कराया जाए। तात्पर्य यह कि भगवान श्रीराम और माता सीता का शुभ विवाह सनातन धर्म की रीतियों और परंपराओं के अनुरूप संपूर्ण विधि-विधान के साथ तो शुभ मुहूर्त में 'विवाह पंचमी' के दिन ही संपन्न हुआ था,लेकिन अपने गुरु महामुनि विश्वामित्र एवं भाई लक्ष्मण जी के साथ माता सीता के विवाह हेतु महाराज जनक द्वारा आयोजित स्वयंबर में पहुंचे भगवान श्रीराम ने जिस दिन भगवान शिव का धनुष तोड़ा था, वास्तव में महाराज जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार जगजननी माता सीता उसी दिन जगन्नायक भगवान श्रीराम की अर्द्धांगिनी हो गई थीं।

ब्रह्मादि देवता साक्षी बने थे- कल्पना कीजिए कि जब हमारे सांवरे सरकार भगवान श्रीराम और माता जानकी दूल्हा-दुल्हन बने होंगे तो कैसा दिव्य और भव्य दृश्य रहा होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम दूल्हा और माता सीता दुल्हन बन कर विवाह के बंधन में बंध रहे थे, तो समस्त देवी, देवतागण उस आयोजन के साक्षी बनने के लिए लालायित हो रहे थे। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्रह्मदेव अपने चारों मुखों के आठों नेत्रों से, कुमार कार्तिकेय जी अपने सभी बारहों नेत्रों से और देवराज इंद्र अपने समस्त सहस्त्र नेत्रों से उस दिव्य और भव्य आयोजन को आरंभ से लेकर अंत तक देखे और धन्य हुए थे।

विशेष पूजन-मंत्र

ऊं जनकनंदिन्यै विद्महे, भूमिजायै धीमहि। तन्नो सीताः प्रचोदयात्।।

ऊं जानकी वल्लभाय नमः

ऊं आपदाम हर्तारम दातारं सर्व सम्पदाम, लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नामाम्यहम, श्री रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः

ऊं दाशरथये विद्महे जानकी वल्लभाय धी महि। तन्नो रामः प्रचोदयात्।।

तौ भगवानु सकल उर बासी। करिहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि कें जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू।।

पूजन-विधि

विवाह पंचमी के दिन प्रातः उठकर नित्यकर्म से निवृत हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

पूजा के समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें।

पूजा की चौकी पर लाल रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाकर भगवान की प्रतिमा या चित्र विराजित करें।

भगवान श्रीराम को पीले और माता सीता को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें।

धूप-दीप प्रज्वलित कर भगवान का ध्यान करें।

उसके बाद श्रीराम और माता सीता को तिलक लगाकर उन्हें फल-फूल, नैवेद्यादि अर्पित करें।

पूजा के दौरान बालकाण्ड में दिए गए विवाह प्रसंग का पाठ करें।

संभव हो तो संपूर्ण श्रीरामचरित मानस का पाठ करें।

तत्पश्चात् सुख-समृद्धि की कामना करते हुए भगवान श्रीराम और माता सीता की आरती करें।

पूजा के बाद योग्य ब्राह्मण को दक्षिणादि प्रदान करें एवं दीन-दुखियों को दान करें।

विवाह पंचमी के कुछ प्रमुख सार्थक उपाय

शास्त्रों के अनुसार विवाह पंचमी केदिन भगवान श्रीराम और माता सीता की प्रतिमा अथवा तस्वीर स्थापित कर विधि-विधान से उनका पूजन करने के बाद कल्याणकारी 'जानकी मंगल'स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। वहीं, इस दिन लाल रंग की स्याही वाली कलम से किसी कॉपी पर अथवा अनार की कलम से अष्टगंध से बनी स्याही के उपयोग से भोजपत्र पर कम-से-कम 108 बार भगवान श्रीराम का नाम लिखने सेतमाम अनिष्ट ग्रहों की पीड़ा बेहद सरलता से दूर हो जाती है। यहां तक कि शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों से लंबे समय से ग्रसित रहने वाले व्यक्ति को भी इन उपायों के करने से अनिष्ट ग्रहों की बेहद कष्टकारी पीड़ा से मुक्ति मिलती है।

(इतिश्री)

जब तक सुविधा नहीं मिलती कांग्रेस का सत्याग्रह जनता जनार्दन के लिए जारी रहेगा: उपाध्याय

नर्मदापुरम। विधायक पद के दावेदार रहे गिरजा शंकर शर्मा की बजाए मुख्यालय पर कोई दूसरा सत्याग्रह कैसे कर रहा है..? यह सवाल आज स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्थाओं को लेकर गजेन्द्र तिवारी सहित कुछेक कांग्रेसियों द्वारा जल सत्याग्रह किया जाना खासी चर्चा का विषय है। आम जनता तो आम जनता प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी तक इस पर चटकारे ले रहें हैं, कह रहे है विधानसभा क्षेत्र में जब कांग्रेस ने जब जनहित और जनहितैषी मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी विधायक दावेदार गिरजा शंकर शर्मा की है तो फिर उनके स्थान पर कोई विकल्प क्यों..? इसके पीछे राजनीतिक क्या है। चार साल पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह के गांव जैत में जाकर रेत के मामले में गिरजा शंकर शर्मा नदी में खड़े होकर

सत्याग्रह कर चुके फिर वे सत्याग्रह से पीछे क्यों..? रेत के मामले को लेकर अब किसी सत्याग्रह या आन्दोलन की कोई सुगबुगाहट नहीं ऐसा क्यों..? इटारसी और नर्मदापुरम सरकारी अस्पतालों में चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को समस्या लेकर नर्मदा में खड़े गजेन्द्र तिवारी के साथ नर्मदापुरम मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजकुमार केलु उपाध्याय कुछेक कांग्रेसी साथियों के साथ सत्याग्रह पर डटे हुए हैं। कांग्रेसियों के इस बौने प्रयास से विधायक के भाई गिरजा शंकर जी कहीं असफल विधायक को बचाने का प्रयास तो नहीं कर रहे..? आम जनता पूछ रही है मेडिकल कॉलेज नहीं बना गिरजा शंकर जी का बयान सोलह आने सच है लेकिन उन्होंने यह मुद्दा चुनाव में क्यों नहीं उठाया था..? बहरहाल कांग्रेस के खाते में जनहितैषी बहुत से मामले उठाए जाने के बिखरे पड़े हैं। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा सिपहसालार नहीं जो असफल विधायक की करतूतों को जग जाहिर कर सके। सत्याग्रह में शामिल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजकुमार केलु उपाध्याय ने इस मौके पर कहा कि जनता जनार्दन की जान की रक्षा को लेकर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मिले इसके लिए जब तक सुविधा नहीं मिलती कांग्रेस का सत्याग्रह जनता जनार्दन को लिए जारी रहेगा।

एम्स भोपाल के आयुष विभाग द्वारा भोजपुर गांव में हेल्थ कैंप का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में आयुष विभाग द्वारा भोजपुर गांव में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। प्रो. सिंह वंचित आबादी तक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के प्रबल समर्थक हैं। इस दौरान भोजपुर गांव में शासकीय माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को योग का विशेष सत्र भी कराया गया, जिसमे बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। इसमें कुल 28 बच्चे और शिक्षक शामिल थे। आयुष विभाग की तरफ से मेडिकल ऑफिसर डॉ रंजना पांडेय और योग प्रशिक्षक चंचल सूर्यवंशी उपस्थित रहे।

इस कैंप में सुबह से लेकर शाम तक स्वास्थ्य जांच और योग के

विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। कैंप की शुरुआत योग सत्र से हुई, जिसमें एम्स के योग विशेषज्ञों ने उपस्थित लोगों को कई योगासन सिखाए, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, और प्राणायाम। विशेषज्ञों ने बच्चों को संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधियों के लाभ बताए, ताकि वे जंक फूड और अस्वास्थ्यकर आदतों से दूर रह सकें। कैम्प में योग परामर्श सत्र के साथ आयुष परामर्श और रोगियों को दवा का निःशुल्क वितरण किया गया और जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा लोगों को समग्र स्वास्थ्य सेवा समाधान प्रदान किया गया। कैंप में आए कई लोग गठिया, चिंता और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों से ग्रसित थे। रोगियों की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक रही ।

प्रो. सिंह ने इस स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में आयुष विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और परिणामों को बेहतर बनाने में इस तरह की आउटरीच गतिविधियों को जरूरी बताया, जिससे लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए सशक्त बनाया जा सके। एम्स भोपाल अपने मिशन के तहत दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एम्स के इस प्रयास से भोजपुर गांव के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल और योग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण मिला है, जिससे वे अपनी दैनिक जीवनशैली में सुधार ला सकते हैं।

एम्स भोपाल में 18वीं आईएपी पोस्ट ग्रेजुएट क्विज़ के जोनल राउंड का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में बाल रोग विभाग ने भोपाल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और एमपीआईएपी के सहयोग से 18वीं भारतीय एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) पोस्ट ग्रेजुएट क्विज़ का जोनल राउंड 4 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस आयोजन की अध्यक्षता बाल रोग विभाग की प्रमुख प्रो. (डॉ.) शिखा मलिक ने की। इस क्विज़ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से टीमों ने भाग लिया। सेंट्रल जोन के क्विज़ समन्वयक प्रो. डॉ. महेश महेश्वरी ने प्रतिभागियों और अतिथियों का स्वागत किया और क्विज़ के प्रारूप का परिचय दिया। यह प्रतियोगिता कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली थी, जिसमें जीएमसी हैदराबाद विजेता और जीआरएमसी ग्वालियर उपविजेता रहें। विजेता टीम अब 62वीं राष्ट्रीय बाल रोग सम्मेलन में केंद्रीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी, जो हैदराबाद में आयोजित होगी।

प्रो. सिंह ने विजेता टीम को बधाई दी और इस कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, यह क्विज़ केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं है, बल्कि यह युवा चिकित्सकों को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने और बाल चिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में अपनी समझ को बढ़ाने का एक मंच प्रदान करता है। इस तरह के कार्यक्रम चिकित्सा समुदाय में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देते हैं।

भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने का फैसला, कांग्रेस का प्रदर्शन

पूर्व मंत्री बोले- गरीबों से घर छीन रही सरकार; आशंका- बिल्डर को बेचेगी प्लॉट

भोपाल। भोपाल को झुग्गी मुक्त करने के लिए एक बार फिर प्रयास शुरू हुए हैं। पहले फेस में वल्लभ भवन के आसपास की झुग्गियां हटेंगी। इसके लिए सर्वे पूरा हो गया है। इसी बीच गुरुवार को कांग्रेस सड़क पर उतर गई। पांच नंबर स्टॉप में कांग्रेसियों ने धरना दिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये झुग्गी मुक्त नहीं, गरीबों को आवास मुक्त करने का फैसला है। इसके विरोध में सड़क से लेकर विधानसभा और कोर्ट तक जाएंगे।

सुबह 11 बजे से शुरू हुए धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। धरने में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस नेता मुकेश नायक, अरुण श्रीवास्तव, विभा पटेल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी, पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान आदि शामिल हुए।

सरकार नहीं मानी तो विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे- पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, सरकार ने भोपाल को झुग्गी मुक्त करने का ऐलान किया है। बिना बताए सर्वे चल रहे हैं, चाहे दुर्गा नगर,

भीमनगर, ओम नगर, वल्लभ नगर हो...। पहले कह रहे थे कि जहां झुग्गी है, वहीं बसाएंगे, लेकिन वल्लभ नगर में मल्टी बनाने से वल्लभ भवन से ऊंची होने का तर्क दे रहे हैं। जहां से झुग्गी हटाएंगे, वहीं पर मल्टी बनना चाहिए। हमें आशंका है कि सरकार बिल्डरों को प्लॉट बेच देगी। इसका हम विरोध कर रहे हैं। पहले सड़क पर उतरेंगे, फिर भी सरकार नहीं मानी तो विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे और हाईकोर्ट में भी जाएंगे।

पहले पक्के मकान बनाकर दें, फिर हटाएं- नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष जकी ने कहा, बीजेपी ने पहले झुग्गी वालों से वोट ले लिए, लेकिन अब झुग्गी को तोड़ने पर आमदा है। गरीबों को घर से बेघर कर रहे हैं। यह सरकार की सही नीति नहीं है। पार्षद गुड्डू चौहान ने कहा, सम्राट अशोकनगर नगर, दुर्गा नगर को हटाने के लिए सरकार सोच रही है। हमारी मांग है कि सरकार झुग्गी के लोगों से बात करे। यहां साल 1984 से पट्टे पर लोग रह रहे हैं। जो लोग जहां रह रहे हैं, उन्हें वहीं पर पक्के मकान बनाकर दिए जाएं। प्रदर्शन में पार्षद देवांशु कंसाना, ब्लॉक अध्यक्ष ओमप्रकाश रजक, योगेश सराठे, दिलीप लालवानी आदि भी मौजूद थे।

2 महीने पहले सीएम ने की थी मीटिंग- भोपाल को झुग्गी मुक्त करने के लिए करीब 2 महीने पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने मीटिंग की थी। उन्होंने झुग्गियों को हटाने के लिए विस्तृत प्लान बनाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि पहले भवन तैयार करें। फिर झुग्गियों को खाली कराएं, ताकि लोगों को परेशानी न हो।

पुणे-दानापुर एक्सप्रेस में सामान्य एवं स्लीपर कोच वृद्धि से यात्रियों को मिली सुविधा

भोपाल। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में, भोपाल मंडल के इटारसी एवं खिरकिया स्टेशन से होकर गुजरने वाली गाड़ी संख्या 12149/12150 पुणे-दानापुर-पुणे एक्सप्रेस में यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कोच संयोजन को परिवर्तित करते हुए एक स्लीपर कोच और एक सामान्य श्रेणी कोच स्थायी रूप से बढ़ाए गए हैं। अब इस गाड़ी का नया कोच संयोजन के अनुसार 02 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी कोच, 06 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी कोच, 07 शयनयान श्रेणी कोच, 04 सामान्य श्रेणी कोच, 01 पेंट्री कार, 01 जनरेटर कार, 01 एसएलआरडी और 02 पार्सल वैन। इस बदलाव के बाद गाड़ी में कुल 23 कोच होंगे। यह स्थायी बदलाव यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाएगा।

निर्मल आनंद

रमेश रंजन त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

दो हजार चौबीस की विदाई

याद रखें, सन् दो हजार चौबीस का आखिरी महीना बीत रहा है, और कुछ ही दिन में यह लाजवाब साल हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। बधाई हो, आपने उम्र का एक वर्ष और जी लिया। यह साल अनेक मामलों में अद्वितीय है। जैसा हरदम होता है, दुनिया में बहुत सी घटनाएं हुईं। अपनी बात करें कि दो हजार चौबीस ने हमें क्या दिया, तो बड़ी बात यह कि इसने हमें संसार में हो रहे बदलाव का साक्षी बनाया, लेकिन पृथ्वी को अलविदा कहने के समय में तीन सौ पैंसठ दिनों की कटौती भी कर दी। दूसरी ओर हमारी बुजुर्गियत के खजाने में अनुभव के बारह महीनों की दौलत का इजाफा कर दिया। परिवार में अनेक तरह के अवसर उपस्थित हुए। नए मेहमान आए तो पुराने विदा भी हुए। कभी खुशी तो कभी गम के पल आए। अच्छी और बुरी घटनाएँ यादों की किताब में दर्ज हो गईं। आंसू और मुस्कान आते-जाते रहे।

आसपास की बात करें तो किसी पर गमों का पहाड़ टूटा और कहीं खुशियाँ छप्पर को फाड़कर आईं। ऊपरवाले का न्याय पहले भी समझ में नहीं आता था, इस साल भी नहीं आया। सो, बुजुर्गों की मानकर हर हाल में आसमानवाले के शुक्रगुजार बने रहे। दूसरों को देखकर कुछ नहीं सीखा, अपने ऊपर बीतने की राह ताकते रहे। लोग बेवकूफ बनाते रहे, इससे अधिक ताज्जुब की बात यह है कि हम बेवकूफ बनते रहे। बेवकूफी का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि हम किसी को बेवकूफ नहीं बना पाए। इस बेवकूफी में संतोष ढूँढ लेना बेवकूफी है या होशियारी, पता नहीं।

इस वर्ष खबरों की भीड़ में तीसरे विश्वयुद्ध का हौवा खड़ा होता रहा लेकिन कुछ कर नहीं पाया। कुछ मुल्क नल के पानी को लेकर लड़ने वाली महिलाओं की हाथापाई की याद दिलाते रहे। 'पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब' जैसे मुहावरे भी पहले की तरह ओलंपिक जैसी खेलों की बड़ी प्रतियोगिताओं के आयोजन पर असर नहीं डाल पाए। दुनिया में बहुत से खिलाड़ी खेलों के दम पर नवाबी झाड़ते रहे। राजनीति, युद्ध और खेल दोनों की प्रशंसक बनी रही। कभी खेलों में घुसपैठ करती तो कभी मैदान-ए-जंग में डट जाती। सियासत का अपना अड्डा तो है ही धमाचौकड़ी मचाने के लिए। वहाँ का हाल जबरदस्त रोचक रहा। उठापटक, शह और मात के टूर्नामेंट आए दिन आयोजित होते रहे। 'प्रेम और युद्ध में सब जायज है' कहावत के चलते दुनिया में सबकुछ जायज ही हो रहा है क्योंकि चारों ओर या तो युद्ध हो रहा है या प्रेम।

उस दिन मेरी भेंट सन् दो हजार चौबीस से हो गई। वह अपना बोरिया-बिस्तर समेट रहा था। लगभग पूरे सामान की पैकिंग हो चुकी थी। बहुत थोड़े आइटम बचे थे। मैंने शेष बची अवधि में ताकझांक करने की कोशिश की तो उसने रोक दिया, बोला- 'आनेवाले समय को पहले से देखने का अधिकार किसी को नहीं।' मैं ठिठक गया। मेरी शालीनता से प्रभावित होकर वह अपना दुखड़ा सुनाने लगा- 'मुझे प्रकृति ने तीन सौ छियासठ दिन और इतनी ही रातों की उम्र बख्शी थी। मैंने अपनी आयु पूरी कर ली है। अब मैं दुनिया से हमेशा के लिए विदा लूँगा। इतिहासकार निस्पृह भाव से मेरा आकलन करें, यही इल्तिजा है। इतिहास निर्मम रहे, कोई बात नहीं, बस पक्षपात कर मुझे दोषी न ठहराए क्योंकि मैं तो अनंत कालखंड का अदना सा हिस्सा हूँ जो खुद कुछ नहीं करता, 'महाभारत' सीरियल के 'समय' की तरह साक्षीमात्र हूँ। करनेवाली या तो प्रकृति है या इंसान। अच्छा या बुरा, सही अथवा गलत सापेक्ष शब्दावली है जिसे मनुष्यों ने रचा है। मेरा रोल केवल इतना है कि घटनाएं मेरे समय के टुकड़े में घटित हुईं। घटनाएं पहले भी होती रही हैं और आनेवाले सालों में भी होंगी। इतना याद रखें।' आदत के मुताबिक मैं आकलन करने लगा कि दो हजार चौबीस की बातों में सच्चाई कितनी है और वाकचातुर्य कितना? कृपया इस काम में मेरी मदद करें।

राइट क्लिक

किसानों को बार-बार दिल्ली कूच क्यों करना पड़ता है?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं। संपर्क- 9893699939 ajaybokil@gmail.com

किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर तीसरी बार देश की राजधानी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली कूच के पहले ही आंदोलनकारी किसान संगठनों में फूट पड़ गई है। उधर केन्द्र व भाजपा शासित राज्य सरकारें किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित मानकर खारिज करती रही हैं तो किसानों का मानना है कि सरकार उनकी मांगों को मानना ही नहीं चाहती। देश की राजधानी के पास तीसरी बार हो रहे, इस किसान आंदोलन के औचित्य को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हाल में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री से जवाब तलब कर नई सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि किसानों की मांगों को लेकर आखिर सरकार कर क्या रही है? मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान संकट में है और आंदोलन कर रहे हैं। यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है। सरकार को आत्मावलोकन की जरूरत है। क्या किसानों से कोई वादा किया गया था? क्या वह पूरा नहीं हुआ? इसी कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान भी मौजूद थे। किसान आंदोलन के पीछे कौन से तत्व हैं, इसे समझने के साथ-साथ इस बात का विश्लेषण भी जरूरी है कि किसान जो मांगें लगातार करते आ रहे हैं, उनका स्थायी समाधानकारक हल क्यों नहीं होता, किसानों को बार बार दिल्ली कूच क्यों करना पड़ता है और यह भी कि क्या इस तरह तकरीबन हर साल किसानों का आंदोलन करना सुनियोजित एजेंडे का हिस्सा बन चुका है?

देश में किसान आंदोलन की शुरूआत 2020 में कोरोना प्रकोप के दौरान ही मोदी सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों के विरोध में हुई थी। यह देश में अब तक का सबसे लंबा चला आंदोलन था। नतीजा यह हुआ कि मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। हालांकि सरकार का एक कदम पीछे खींचना राजनीतिक दृष्टि से भाजपा के लिए फायदेमंद ही साबित हुआ, क्योंकि इसने कृषि कानून विरोधी आंदोलन की धार को ही कुंद कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि किसानों की सारी समस्याओं का समाधान हो गया है।

दरअसल किसानों की जायज समस्याएं और उनका निदान ऐसे आंदोलनों तथा उस पर होने वाली राजनीति के धुंध में खो जाता है। किसानों का हफ्तों धरने पर बैठना, रास्ते रोकना, आंदोलन का किसानों की आंतरिक राजनीति का शिकार होना, सत्तापक्ष और विपक्षी सरकारों द्वारा इसका ट्रीटमेंट अपने अपने राजनीतिक हितों के नजरिए से करना, एक आम और गरीब किसान का ऐसे आंदोलनों से दूर ही रहना, प्रशासन द्वारा आंदोलनकारी किसानों से कभी नरमी तो कभी सख्ती से निपटना, केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह के आंदोलन को प्रायोजित मानकर इसकी उपेक्षा करना, इन किसान आंदोलन के स्थायी बिंदु बन चुके हैं। सवाल यह भी उठते रहे हैं कि खेती के मौसम में किसान इतनी लंबी अवधि तक धरने पर कैसे बैठे रह सकते हैं? उनके आंदोलन का हिस्सा बनने पर खेती का काम कौन संभालता है? आंदोलन के चलते अगर खेती पर ध्यान न दिया तो उससे होने वाला नुकसान एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदी नहीं होने से होने वाली हानि की तुलना में अधिक नहीं है? इसी के साथ यह सवाल भी जुड़ा है कि किसान को लगातार मुश्किल में डालकर सरकार आर्थिकी को बुलेट की रफ्तार से आगे कैसे ले जाएगी?

ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसानों की कोई मांग नहीं मानी हो, लेकिन देश में किसी एक वर्ग को ही सर्वस्व मानकर उसे संतुष्ट करने की राह पर तो कोई सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। इस समूची व्यवस्था का किसान एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं, इससे इंकार नहीं, लेकिन किसान और वो साधन सम्पन्न किसान ही सब कुछ हों, ऐसा भी नहीं है।

ऐसा लगता है कि तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन अपने ही अंतर्विरोधों का शिकार ज्यादा हो गया है। इस बार भी 40 किसानों के छाता संगठन संयुक्त किसान मोर्चे (एसकेएम) ने किसान आंदोलन से दूरी बना ली है। उसका कहना है कि जो कुछ हो रहा है, इसमें उनकी राय नहीं ली गई है। इसी तरह किसान नेता राकेश टिकैत भी इस आंदोलन से दूर है। हरियाणा के किसान संगठनों ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। हालांकि इस बार भी किसानों की मुख्य मांग फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की है।

आंदोलनकारी किसानों की एक बड़ी समस्या, इस आंदोलन की ताकत का राजनीतिक रूपातंरण न होने की है। मोदी सरकार और भाजपा आंदोलन की इस कमजोरी से वाकिफ हैं। यह भी अपने आप में आश्चर्यजनक है कि जो किसान धूप, बारिश और सर्दी में भी डटकर आंदोलन में खड़ा होता है, चुनावी राजनीति में उसका व्यवहार कुछ और होता है। मसलन तीन कृषि कानून वापसी के पीछे भाजपा का यह भय था कि इसका असर 2022 में हुए यूपी के विधानसभा चुनाव पर न पड़े। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी इसमें शामिल थे। लेकिन चुनाव नतीजे में भाजपा फिर सत्ता में लौट आई। सबसे हैरान करने वाला परिणाम तो पंजाब विधानसभा चुनाव का था, जहां किसानों के संगठन संयुक्त समाज मोर्चा ने 104 प्रत्याशी चुनाव में खड़े किए, लेकिन इनमें कोई भी जमानत भी नहीं बचा पाया। यह मोर्चा भी किसान आंदोलन में सक्रिय था हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे ने चुनाव से दूरी बना ली थी। हाल में हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने भी यही साबित किया। बाकी राज्यों के किसानों की इस आंदोलन में भागीदारी नहीं के बराबर है, जबकि समग्रता में देखें तो देश में किसानों की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं।

अब सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों की समस्या का मुद्दा उठाकर केन्द्र सरकार को कठघरे में खड़ा क्यों किया? क्या उन्हें लगता है कि मोदी सरकार किसानों की मांगों को केवल राजनीतिक चश्में से देखती है या फिर उन्हे लगा कि किसानों की जायज मांगों के हल के लिए कोई ठोस उपाय अभी भी नहीं किए गए हैं? उपराष्ट्रपति की पीड़ा इसलिए भी वाजिब है, क्योंकि उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना। यह भी संभव है कि वो सरकार पर दबाव बनाना चाहते हों कि उन्हें इसी पद पर दूसरा कार्यकाल मिले। लेकिन इससे यह सवाल डायल्यूट नहीं होता कि किसान आंदोलन पूरी तरह प्रायोजित है और इसका एक मात्र मकसद सरकार को ब्लैकमेल करते रहना है। उपराष्ट्रपति के कहने का आशय यही है कि सरकार किसान संगठनों से बात तो करे। संवाद से ही कुछ समाधान निकलने की संभावना है। इस बीच यूपी सरकार ने किसानों के मुद्दे के निराकरण के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी है। समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। उधर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान के सामने भी चुनौती है कि वो किसानों की समस्या का निदान कैसे करते हैं? कर भी पाते हैं या नहीं?

टी.बी. लाइलाज बीमारी नहीं: मुख्यमंत्री यादव

कोई भी प्रभावित व्यक्ति, जांच और इलाज से वंचित न रहे

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2018 में देश को टी.बी. (क्षय रोग) से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। लोगों की जिंदगी बचाने के प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस अभियान में सहभागिता कर हम सब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। देश को टी.बी. मुक्त करने के लिए, देश के 347 जिलों में 100 दिवसीय नि-क्षय शिविर अभियान चलाया जा रहा है। इनमें मध्यप्रदेश के 23 जिले अलीराजपुर, अनूपपुर, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, सीहोर, सिवनी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन और विदिशा शामिल हैं।

टी.बी. से मुक्ति के अभियान में प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति एक कार्यकर्ता है- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी की सक्रिय सहभागिता से कोई भी प्रभावित व्यक्ति टी.बी. की जांच और इलाज से वंचित नहीं रहेगा। टी.बी लाइलाज बीमारी नहीं है, टी.बी. का इलाज होता है, टी.बी. से डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब सक्रियता के साथ इस अभियान में भागीदारी करें। हमारे आसपास कोई भी टी.बी. की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति हो तो उसे इस अभियान का हिस्सा अवश्य बनाएं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में लोगों का जीवन बचाने के लिए आरंभ, इस अभियान में प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति एक कार्यकर्ता है। हम सब मिलकर टी.बी. से प्रभावित व्यक्तियों को इस रोग से मुक्त कराने का प्रयास करें। सबके प्रयासों से देश को टी.बी. मुक्त कर, प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प को साकार करने में निश्चित ही सफलता मिलेगी।

बच्चों को अवश्य पिलाएं दो बूंद जिन्दगी की - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 8 से 10 दिसंबर तक प्रदेश के 16 जिलों क्रमशः भिण्ड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, सतना, श्योपुर, टीकमगढ़ और विदिशा में पल्स पोलियो अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने प्रदेश के समस्त नागरिकों से आहवान किया कि सब मिलकर परिवारों को प्रोत्साहित करें और नवजात बच्चों से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की 'दो बूंद जिन्दगी की' जरूर पिलाएं, जिससे भविष्य में पोलियो से पूर्ण मुक्ति मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम सब जानते हैं कि पोलियो बच्चों में आजीवन दिव्यांगता पैदा करता है, यह बहुत कष्टप्रद बीमारी रही है। इससे बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। वैक्सीन से ही बच्चे और भावी पीढ़ियां सुरक्षित रहती हैं।

डेढ़ सौ बच्चों की आज से फ्री कोचिंग

भोपाल में यूपीएससी-एमपीपीएससी की तैयारी कराएंगे अफसर; मैरिट से हुआ है सिलेक्शन

भोपाल (नप्र)। भोपाल में यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) और एमपीपीएससी (मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग) की फ्री कोचिंग शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने कोचिंग का शुभारंभ किया। जिन डेढ़ सौ बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी, उनका सिलेक्शन मैरिट के जरिए हुआ था।

शासकीय हमीदिया आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज गिन्नौरी में बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। बता दें कि फ्री कोचिंग की कुल 150 सीटों के लिए 900 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ये रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में किए गए थे। 24 नवंबर को हुए टेस्ट में 628 स्टूडेंट्स बैठे थे। इस हिसाब से प्रत्येक 4 में से 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन कोचिंग के लिए किया गया।

रिटायर्ड स्पेशल डीजी भी पहुंचे- निःशुल्क कोचिंग क्लॉसेस के शुभारंभ मौके पर मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव गुप्ता और विशिष्ट अतिथि रिटायर्ड स्पेशल डीजी मुकेश जैन थे। यह कोचिंग एनजीओ 'आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा' के सहयोग से शुरू की गई है।

अन्य छात्रों का सिलेक्शन भी होगा- एनजीओ से जुड़े राम लखन मीणा ने बताया, अभी डेढ़ सौ बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। आवश्यक होने पर जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी।

गरीब कन्याओं की शादी, हेलिकॉप्टर से आया विधायक का बेटा

विधायक मधु बोले- पिताजी की इच्छा थी, बेटा बहनों की डोली को कंधा देने हेलिकॉप्टर से जाए

विधायक ने अपने खर्च से 61 जोड़ों का विवाह कराया

आगर मालवा (नप्र)। आगर-मालवा से भाजपा विधायक मधु गेहलोत ने अपने खर्च से 61 जोड़ों का विवाह कराया। कन्यादान करने के साथ उन्होंने घराती और बारातियों की जमकर खातिरदारी की। पूरे कार्यक्रम की खास बात ये रही की विधायक का बेटा गरीब कन्याओं के विवाह समारोह में अपने परिवार सहित इंदौर से आगर-मालवा (144 किलोमीटर) हेलिकॉप्टर से आया।

विधायक मधु गहलोत के पुत्र लक्की सिंह, उनकी पत्नी और अन्य परिजन समारोह में सम्मिलित होने हेलिकॉप्टर से इंदौर से यहां पहुंचे। लक्की सिंह की शादी दो दिन पहले 3 दिसंबर को इंदौर जिले के बेटमा में हुई है। 61 युवक-युवतियों का विवाह भी विधायक ने उसी उपलक्ष्य में कराया है। स्थानीय नवीन कृषि उपज मंडी में आयोजित इस कार्यक्रम में आगर विधानसभा क्षेत्र के हर परिवार को आमंत्रित किया गया था। विधायक ने 61 नव दंपत्तियों को उपहार में गृहस्थी का पूरा सामान भी दिया है। जिसमें फ्रिज, टीवी, सोफा, अलमारी और बर्तन शामिल हैं। बड़े पैमाने पर भोज की व्यवस्था भी उन्होंने की थी।विधायक के बेटा लक्की परिवार सहित इस हेलिकॉप्टर से विवाह समारोह में आगर-मालवा आया।

पिता के दोस्त का हेलिकॉप्टर- इस अवसर पर विधायक मधु गहलोत ने कहा कि वे बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें 61 बहनों का बड़ा भाई बनकर उनका कन्यादान करने का अवसर मिला। मधु गहलोत से जब यह पूछा गया कि उनका बेटा और परिवार हेलिकॉप्टर से यहां पहुंचे इसका कोई विशेष कारण है तो उन्होंने कहा,उनके पिता पिरालाल गहलोत के मित्र का यह निजी हेलिकॉप्टर है, उनकी इच्छा थी कि लक्की सिंह और उनकी पत्नी 61 निर्धन बालिकाओं की डोली को कंधा देने हेलिकॉप्टर से जाएं।

मेघा भांप चुकी थी एएसआई जीजा के खतरनाक मंसूबे

मर्डर से 6 दिन पहले मंडला-बालाघाट एसपी को लिखा लेटर; बोली-मुझे जान का खतरा

भोपाल (नप्र)। भोपाल में डबल मर्डर के आरोपी एएसआई योगेश मरावी के मंसूबे को उसकी साली मेघा उइके पहले ही भांप गई थी। उसे आशंका थी कि योगेश कुछ गलत कर सकता है। वारदात से 6 दिन पहले 27 नवंबर को मेघा ने अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से बालाघाट और मंडला के एसपी को शिकायत भी भेजी थी। इनमें बताया था कि योगेश ने घर-ऑफिस आकर हमारे बारे में लोगों को गंदी बातें बोली हैं। उससे जान का खतरा है।

मेघा के मोबाइल में शिकायत की पीडीएफ कॉपी मिली है। यह बालाघाट आईजी के नाम है। इसमें मेघा के साइन के साथ 27 नवंबर 2024 की डेट तो है लेकिन पुलिस की सील नहीं है। इतना ही नहीं, मेघा उईके इसके पहले 21 नवंबर को भी जीजा योगेश मरावी के खिलाफ भोपाल के एमपी नगर थाने में शिकायत दर्ज करा चुकी थी। मेघा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में वित्त लेखाधिकारी थी। 3 दिसंबर को सुबह करीब 11 बजे योगेश घरेलू काम करने आई मेड को धक्का देकर मेघा के फ्लैट में घुस गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।

सत्ता का सर्कस

पूजा स्थल कानून की बाधा जरूरी या मजबूरी

दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

कट्टर हिन्दुत्व जीवी लोग और संगठन अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि 1947 में देश के विभाजन के वक्त सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। मुस्लिमों को भारत में ही रहने का विकल्प देकर गांधी-नेहरू और उनकी कांग्रेस ने बड़ी गलती की है। भारत में जिस तरह से मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं,उसी तरह से पाकिस्तान एवं बांगलादेश में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। अदालत के आदेश से मस्जिदों के वास्तविक स्वरूप का पता लगाने के लिए किए जा रहे सर्वे से मुस्लिम जिस तरह से अपने आपको प्रताड़ित मान रहा है,उसी तरह बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ प्रताड़ना अलग-अलग कारणों से सामने आ रही है। बांग्लादेश के हिन्दुओं के खिलाफ हो रही उत्पीड़न की कार्यवाही के विरोध में भारत के हिन्दुओं ने जबरदस्त एकजुटता का प्रदर्शन किया है। पिछले दो दिन से पूरे देश में कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन की कार्यवाही हो रही है। कई जगह सफल बंद भी देखने को मिला। हिन्दुओं की इस एकजुटता का इकलौता श्रेय राष्ट्रीय स्वयं सेवक को ही जाता है। संघ के स्वयंसेवकों ने इसके लिए काफी मेहनत की है। वैसे ही जैसे 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से हर हिन्दू परिवार को जोड़ने की कोशिश की थी। इसका लोकसभा चुनाव में लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला था। यह और बात है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे का अंडर करंट होने से वह चार सौ पार के अपने लक्ष्य को नहीं पा सकी थी।

भाजपा लोकसभा चुनाव में यदि चार सौ पार कर जाती तो क्या वह संविधान में कोई बड़ा बदलाव कर पाती? काल्पनिक तौर पर यह माना भी जा सकता है और नहीं भी। भाजपा चार सौ पर जाती तो वह जनमत को आधार बनाकर किसी भी तरह का संवैधानिक बदलाव कर सकती थी। उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। राजीव गांधी ने भी तो शाहबानो प्रकरण में बदलाव किया ही था। अभी भी देश में जो सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है वह पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को लेकर है। इस मुद्दे पर बहस और अदालती कार्यवाही का दरवाजा भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे डी. वाय. चंद्रचूड़ की उस टिप्पणी के बाद खुला है जिसमें उन्होंने कहा कि 1991 का अधिनियम 15 अगस्त, 1947 से पहले की पूजा स्थल की स्थिति की जांच पर रोक नहीं लगाता है, जब तक कि इसकी प्रकृति को रूपांतरित या बदलने का कोई इरादा न हो। यह व्याख्या अयोध्या फैसले में लिए गए रूख से अलग है, जिसे कथित तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही लिखा था। इस टिप्पणी से पहले 2019 में अयोध्या के रामलला के मंदिर के बारे में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगता था कि देश सांप्रदायिक जहर की राजनीति से मुक्त हो जाएगा। लेकिन, अंग्रेजों की फूट डालों राज करों की नीति मौजूदा नेतृत्व की राजनीतिक मजबूरी बन गई है। ऐसा लगता है कि निचली अदालतों ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों की व्याख्या इस प्रकार की है कि पूजा स्थल की मूल प्रकृति को निर्धारित करने के लिए किए जाने वाले ऐसे मामले, भले ही उसमें बदलाव न किया जा सके, 1991 के अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं हैं।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 संसद में जिस दौर में पेश किया गया था,उस दौर और राजनीति को जाने बगैर इसके उद्देश्य और आवश्यकता के बारे में नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। अदालतें कानून की संवैधानिक वैधानिकता को ही देखती हैं। आमतौर पर कानून बनाए जाने की परिस्थितियों से उसका कोई सरोकार नहीं होता है। जिस दौर में यह कानून लोकसभा में पारित हुआ ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथयात्रा निकाली। इसे 29 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 23 अक्टूबर को उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने का आदेश दिया था जनता दल के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने। इस गिरफ्तारी का असर ये हुआ कि केंद्र में जनता दल की वीपी सिंह सरकार गिर गई, जो भाजपा के समर्थन से चल रही थी। इसके बाद वीपी सिंह से अलग होकर चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन ये भी ज्यादा नहीं चल सकी। नए सिरे से चुनाव हुए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर-मस्जिद विवाद उठने लगे थे। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए ही नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। एक साल बाद, दिसंबर 1992 में, विश्व हिन्दू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया गया, जिससे पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके की भारी आलोचना की गई, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाली यूपी सरकार को अनुमति देना भी शामिल था, जिसने सुरक्षा उपायों की निगरानी के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था।

कानून लागू होने के लगभग 42 साल बाद इसकी संवैधानिक वैधता पर विचार करने के लिए यदि याचिकाएं दायर होती हैं तो इसकी वजह जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा की गई टिप्पणी बड़ी वजह है। जबकि राम मंदिर के फैसले के समय अदालत का रूख पूरी तरह स्पष्ट था। पूजा स्थल विधेयक को लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर अपने फैसले में कहा था कि ऐतिहासिक गलतियों को कानून हाथ में लेकर ठीक नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक उपासना स्थलों के स्वरूप को बनाए रखते हुए संसद ने स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित किया है कि इतिहास और उसकी गलतियों का उपयोग वर्तमान और भविष्य को दबाने के लिए उपकरण के रूप में नहीं किया जाएगा। यह टिप्पणी पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का संदर्भ देती है, जो 15 अगस्त 1947 के बाद से किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने की मांग को प्रतिबंधित करता है और ऐसा प्रयास करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान करता है। 1991 में यह अधिनियम पारित हुआ और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके महत्व को दोहराया।

अदालत ने राममंदिर को 1991 के अधिनियम से एक अपवाद के रूप में स्वीकार किया क्योंकि यह 1947 से पहले की कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा था। इससे लगा कि देश को सांप्रदायिक जहर से मुक्तङ्क कर दिया है। पर ऐसा हो नहीं सका। मौजूदा हालात ये हैं कि हर महीने कहीं न कहीं से खबर आती है कि यह मस्जिद पहले मंदिर या यह शिवालय था। इसमें बहुत सारे मामले कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अब पुरानी बातों को भूलने का वक्त है। उन्होंने कहा था कि रामलला के साथ भारत का गौरव लौट कर आया है। इसके अलावा हमें सबको साथ लेकर चलना है, अब विवादों से बचना होगा। इसके बावजूद मथुरा में शाही मस्जिद, धार (मध्यप्रदेश) में भोजशाला परिसर, दिल्ली में कुतुब मीनार, लखनऊ में टीली वाली मस्जिद, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मध्य प्रदेश में कमाल-उद-दीन मस्जिद, वाराणसी की धरहरा मस्जिद, बंदायूं की शाही इमाम मस्जिद सहित देश में और कई स्थानों पर विवादों को हवा देने में कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

पंद्रह अगस्त 1947 की तारीख का इतिहास देश की आजादी और विभाजन से जुड़ी हुई है। देश के विभाजन के फलस्वरूप जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसके जख्म शायद ही कभी भरे पाएंगे? सांप्रदायिक नफरत की आग काफी शांत होती दिखती भी नहीं है। इसकी राख में दबी चिंगारी कभी भी शोला बनकर सामने खड़ी हो जाती है। पूजा स्थल अधिनियम में मौजूद अपवाद और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पेश किया गया नया अपवाद, ढेर सारे विवादों को कानूनी और सामाजिक रूप से बढ़ावा दे रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से हल होने और मंदिर बन जाने के बाद लगा था कि भारत धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द्र के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। इसके बावजूद यह मुद्दा सच्चाई नहीं बन सका। अब देश में अलग-अलग स्थानों पर मंदिर-मस्जिद का मुद्दा सुलग रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया था कि देश में केवल काशी और मथुरा की मस्जिदें ही विवादित नहीं हैं, बल्कि इनकी संख्या कहीं ज्यादा है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने अदालत में कहा था कि भारत भर में विवादित मस्जिदों और स्मारकों की संख्या लगभग 50 है। इनमें कुछ प्रमुख ऐसी हैं जहां भविष्य में कभी भी विवाद बढ़ने के आसार बन सकते हैं।

ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर ऐसे विवादों के मद्देनजर कई बार पूजा स्थल अधिनियम में बदलाव की मांग की जा चुकी है, ताकि इस तरह के दफन हो चुके मुद्दों को फिर से नहीं उठाया जाए। नेताओं ने इस मांग को अनसुना कर दिया। इसके विपरीत भाजपा पूजा स्थल अधिनियम 1991 को खत्म किए जाने की मांग कर चुकी है, ताकि देश में बहुत से धार्मिक स्थलों को मुक्त कराया जा सके। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पूजा स्थल कानून 1991 को तत्काल समाप्त करने की मांग उठाई थी। राज्यसभा में उन्होंने आरोप लगाया था कि यह कानून संविधान के तहत प्रदान किए गए हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों के धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है। इससे जाहिर है कि कम से कम भाजपा इस कानून में संशोधन करने या इसे समाप्त करने के पक्ष में है।